04 - वंदे मातरम् पर विवाद क्यों?

05 - राजपथ से संघ ने दिया एकजुटता का संदेश

A Daily News Magazine

इंदौर

सोमवार, 26 जनवरी, 2026

06 - बैतूल के लाड़ले मोहन नागर को मिला पद्मश्री का...

07 - गणतंत्र दिवस- हमारा कर्तव्य

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 117, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

गणतंत्र की रोशनी

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर म.प्र. विधानसभा भवन पर रोशनी की गई। फोटो-प्रवीण वाजपेई

लोकतांत्रिक मूल्यों को हर हाल में बचाना होगा...

विशेष संपादकीय

अजय बोकिल

21वीं सदी की पहली चौथाई की समाप्ति के बाद सारी दुनिया के समक्ष पहली चुनौती विश्व में उन लोकतांत्रिक, शांति, सौहार्द्र, संप्रभुता, साहचर्य और भाईचारे के मूल्यों को बचाने की है, जिनकी बुनियाद पर 20 सदी के उत्तरार्द्ध में एक नई और उम्मीद भरी दुनिया खड़ी की गई थी। ऐसे में हमे हमारे पूर्वजों द्वारा विरासत में सौंपे गए संवैधानिक मूल्यों और एक शक्तिशाली गणराज्य के रूप में भारत की आत्मा को सहेजे रखने की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि ये ही वो मूल्य हैं, जो भविष्य की दुनिया के लिए भी प्रकाश स्तम्भ साबित होंगे।

चिंता की बात यह है कि आज 75 साल बाद उन मूल्यों और सर्वमान्य सिद्धांतों की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिख रही हैं और यह धज्जियां एक ऐसे देश का राष्ट्राध्यक्ष अपनी निजी सनक की खातिर उड़ा रहा है, जो अपने लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों पर पिछली दो सदियों से गर्व करता आया है और खुद को इन मूल्यों का पहरेदार बताता रहा है। विडंबना यह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षक की यह भूमिका अब निर्लज्ज दबंगई में तब्दील हो चुकी है। इसमें निर्वाचित सत्ताधीशों को उनके घर से उठवा लेना, दुनिया के किसी भी हिस्से को अपना बताकर उस पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना और टैरिफ को एक हथियार बनाकर दूसरे देशों के खिलाफ उसका मनमाना इस्तेमाल करना। इसके पहले तक दुनिया में ऐसा आचरण तानाशाहों और निरंकुश राजाओं से ही अपेक्षित होता था। माना जाता था कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जनता के प्रति जवाबदेही होती है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परस्पर सम्मान, उदात्तता और सहिष्णुता की सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर जिस तरह अपनी ताकत के दम पर और कथित 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के नाम पर दादागिरी शुरू की है, वह अमेरिका की प्रतिष्ठा को कम ही करती है।

भारतीय गणराज्य की 76वीं वर्षगांठ पर हमे अपने संवैधानिक मूल्यों की हरसंभव रक्षा का संकल्प दोहराना चाहिए। क्योंकि आज भारत भी ट्रंप के टैरिफ वार, दबंगई और आतंकवाद का शिकार है। हालांकि भारत आज किसी का पिछलग्गू नहीं है, लेकिन दादागिरी और अधिनायकवादी माहौल ने हमारे लिए मुश्किलें जरूर खड़ी की हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय गणराज्य की नींव उन मूल्यों पर रखी थी, जो आज वैश्विक रूप में मानवता का आधार माने जाते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता, समानता, समता, भाईचारा, सभी को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। यही वो आधारभूत तत्व हैं, जिन पर न केवल भारत बल्कि समूची विश्व के कायम रहने का आश्वासन निहित है। दुर्भाग्य से आज इन्ही मूल्यों को तिलांजलि देने की यथासंभव कोशिश हो रही है। स्थापित मूल्यों और संकल्पों की मनमानी व्याख्या कर उन्हें दूसरों पर बलपूर्वक लादने और न मानने पर नष्ट करने की धमकी दी जा रही है। दुनिया में आज लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित नेता ही अधिनायक बनते जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव भी केवल ढोंग और षड्यंत्र बनकर रह गए हैं। जनता से मिली शक्ति को निजी महत्वाकांक्षाओं और सनक की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया के लिए यह स्थिति अपेक्षाकृत नई और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। कानून के शासन को धता बताया जा रहा है। ऐसे में एक सार्थक, सशक्त लोकतांत्रिक गणराज्य ही देश और दुनिया को बचा सकता है।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर 26 जनवरी को 'सुबह सवेरे' कार्यालय में अवकाश रहेगा। अखबार का अगला अंक 28 जनवरी 2026 को प्रकाशित होगा। सभी पाठकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। - सं.

कोई युवा पहली बार वोटर बने तो मिठाई बांटें : मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 130वें एपिसोड में देश के लोगों को संबोधित किया है। इस साल ये पीएम मोदी का पहला मन की बात कार्यक्रम था, जिस दौरान उन्होंने देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

मन की बात में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये 2026 की पहली मन की बात है। कल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी का पर्व हमें हमारे संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- आज 25 जनवरी का दिन भी बहुत अहम है। आज नेशनल वोटर्स डे है।

पद्म पुरस्कार 2026 का हो गया ऐलान

धर्मेन्द्र को पद्म विभूषण, रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान

म.प्र .से मोहन नागर और कैलाशचंद्र पंत को मिला सम्मान

नई दिल्ली (एजेंसी)। गणतंत्र दिवस के पहले केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। दिवंगत एक्टर भट्ट, छत्तीसगढ़ से बुदरी थाटी, ओडिशा से चरण हेम्ब्रम और गुजरात से धार्मिकलाल चुन्नीलाल पांड्या शामिल हैं। गुजरात के मीर हाजीभाई कासमभाई को कला के क्षेत्र में पद्म श्री 2026 से सम्मानित किया जाएगा।

धर्मेंद्र समेत 5 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। झारखंड के पूर्व सीएम दिवंगत नेता शिबु सोरेन और गायिका अलका याज्ञनिक समेत 13 हस्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। वहीं, क्रिकेटर रोहित शर्मा, प्रवीण कुमार, महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, हॉकी प्लेयर सविता पूनिया समेत 113 हस्तियों को पद्मश्री के लिए चुना गया है। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के अंके गौड़ा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2026 का पद्म श्री पुरस्कार दिया जा रहा है। न्यूज एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अनसंग हीरोज कैटेगरी में करीब 45 लोगों को पद्म श्री अवॉर्ड दिए गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश से भगवानदास रैकवार, जम्मू-कश्मीर से बृज लाल

पद्म पुरस्कारः सूत्रों के अनुसार, मध्य प्रदेश, मोहन नागर मप्र.को पर्यावरणविद के क्षेत्र में पद्म श्री 2026 से सम्मानित किया जाएगा। कैलाशचंद्र पंत को साहित्य और शिक्षा मप्र के लिए। इस साल के पद्म पुरस्कारों में पूरे भारत से कई गुमनाम नायकों को सम्मानित किया गया है। इनमें हाशिए पर पड़े पिछड़े और दलित समुदायों, आदिवासी जनजातियों और दूरदराज और मुश्किल इलाकों से आने वाले लोग शामिल हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों, दलितों और आदिवासियों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है - स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका, स्वच्छता, स्थिरता आदि को बढ़ावा देने के लिए काम किया है।

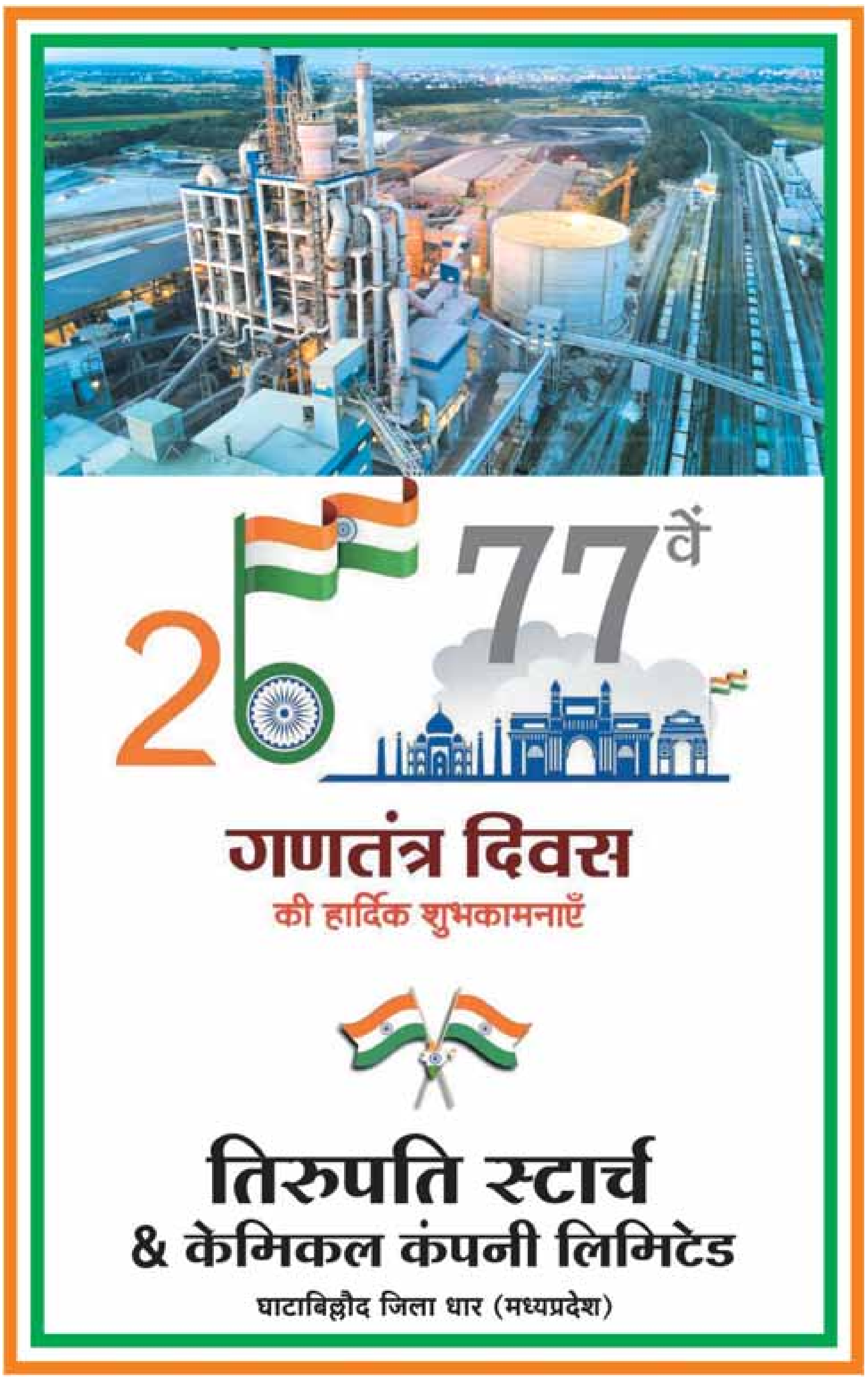

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित ऑडिटोरियम 'नादबृम्ह कंवेंशन सेंटर' का किया लोकार्पण

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कॉलेज में नवनिर्मित आडिटोरियम ''नादबृम्हा कन्वेंशन सेंटर'' का लोकार्पण किया। ऑडिटोरियम में 1400 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा यहां 8 अतिरिक्त हॉल है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर कहा कि आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद यह क्षेत्र शहर का काफी महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। मेडिकल कॉलेज द्वारा 25 वर्षों से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही है। यहां से अध्ययन कर निकले डॉक्टर्स देश-विदेश में उज्जैन का नाम रोशन कर रहे है। प्रदेश का

पहला प्रायवेट मेडिकल कॉलेज बनने का गौरव इसे प्राप्त है। राज्य शासन द्वारा तेज गति से प्रदेश में मेडिकल संस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है। डॉक्टर्स हमारे अमूल्य जीवन की रक्षा करते है। इसी लिए वे ईश्वर के समान होते है। मुख्यमंत्री ने उक्त ऑडिटोरियम की अपनी ओर से बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वे मेडिकल की पढाई की फीस नहीं दे सकते, उन्हें शासन की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डल ऑवर में अस्पताल पहुंचाने के लिए हमने राहवीर योजन प्रारंभ की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सत्यनारायण जटिया ने कहा कि इस कॉलेज से उनका आत्मीय लगाव है। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉ वी.के महाडिक और चेयरमेन डॉ. सुधीर गवारीकर ने अतिथियों का स्वागत किया।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 25°c
न्यूनतम 20°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ सोमवार, 26 जनवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

‘भारत रंग महोत्सव’ का अंतरराष्ट्रीय आयोजन कल 27 जनवरी से

नई दिल्ली। ‘भारत रंग महोत्सव’ (भारंगम / BRM) 27 जनवरी से शुरू होकर 22 फरवरी 2026 तक चलेगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली (एनएसडी) के इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में कुल 277 नाटकों का मंचन होगा। इनमें 136 चयनित और 12 विदेशी नाटक शामिल हैं। नाटकों का प्रदर्शन देश के 40 केंद्रों पर किया जाएगा। साथ ही सातों महाद्वीपों के कम से कम एक देश में भी ड्रामा शोज़ होंगे। शुभारंभ के दिन से एनएसडी का अपना रेडियो, पॉडकास्ट और ओटीटी चैनल भी शुरू होगा’।

थियेटर का महाकुंभ जनता का महोत्सवः एनएसडी के निदेशक चित्तरंजन त्रिपाठी ने यह बात एनएसडी के सम्मुख सभागार में आयोजित प्रेस मीट में कहीं। उन्होंने मीडिया कर्मियों के कुछ अहम सवालों के जवाब भी दिये। त्रिपाठी ने कहा- ‘थियेटर का ये महा कुंभ- जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिये एक अंतरराष्ट्रीय महोत्सव है। यहां पर कई संस्कृतियों और विचारधाराओं का संगम देखने को मिलता है। ज्ञान का आदान-प्रदान होता है’।

विश्व का सबसे बड़ा नाट्य महोत्सवः प्रारंभ में उपाध्यक्ष प्रो. भरत गुप्त ने कहा- ‘भारंगम, विश्व का सबसे बड़ा नाट्य महोत्सव है, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। यह हमारे लोकतंत्र का प्रतीक है। यही महोत्सव की बड़ी विशेषता है, जिस पर ज़ोर दिया जाना चाहिये’। इस अवसर पर नाट्य विद्यालय के रजिस्ट्रार प्रदीप के. मोहंती, प्रो. शांतनु बोस और फेस्टिवल कंट्रोलर सुमन वैद्य भी मौजूद थे। सभी ने भारंगम के 25वें महोत्सव का पोस्टर भी जारी किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रकाश झा ने किया। एनएसडी का रेडियो, पॉडकास्ट और ओटीटीः त्रिपाठी ने कहा, ‘एनएसडी के अपने रेडियो-पॉडकास्ट की औपचारिक घोषणा महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर होना थी, लेकिन इस पर पूछे गये सवाल की वजह से वे यह जानकारी साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रेडियो, पॉडकास्ट और ओटीटी चैनल के लिये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास नाटकों का विशाल ख़ज़ाना है, जिसका लाभ इन प्रसार माध्यमों से दुनिया भर के नाट्य प्रेमियों को मिल सकेगा’।

भारत रंग

(शकील अख़्तर)
सृजनधर्मी लेखक-पत्रकार हैं

‘जश्न-ए-बचपन’ और ‘बाल संगम’ की वापसीः त्रिपाठी ने कहा कि इस बार के महोत्सव में जश्ने बचपन और बाल संगम की प्रस्तुतियां भी होंगी। बाल रंगमंच की गतिविधियां 2019 के बाद से थमी हुई थीं, लेकिन 25वें संस्करण से इनकी वापसी हो रही है। इनमें आदिवासियों की कला और शिल्प का ‘आदि रंग महोत्सव’ भी शामिल है। उन्होंने बताया, 2026 के इस संस्करण में कई देशी और विदेशी सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग मिला है। इनमें विभिन्न अकादमियां भी शामिल हैं। संस्कृति मंत्रालय के अधीन सभी अकादमियों-विभागों में बेहतर समन्वयन है’।

बुक माय शो पर उपलब्ध होंगे टिकटः त्रिपाठी ने बताया कि महोत्सव के टिकट ‘बुक माय शो’ से ही उपलब्ध होंगे। यह एक बेहतर और सर्वसुलभ डिजिटल व्यवस्था है। टिकट दरों में मामूली वृद्धि की गई है, जो केवल मंच के सामने की पंक्तियों (front rows) पर लागू होगी। इससे विद्यालय को कुछ अतिरिक्त आय होगी, जो वर्तमान टिकट दरों की तुलना में बहुत कम है। उन्होंने कहा, हम भी चाहेंगे कि हमारे टिकट भी ‘ब्रॉडवे थियेटर’ की तरह ऊंचे दामों के हों, कला को उचित मान और दर्जा मिले !

चयन प्रक्रिया और भाषाई विविधताः त्रिपाठी ने कहा- ‘इस बार देश भर से 817 और विदेशों से 34 आवेदन प्राप्त हुए थे। दो राउंड की स्क्रीनिंग के बाद चयन समितियों के 90 सदस्यों ने 136 नाटकों का चयन किया। सभी के लिये एक सी प्रक्रिया अपनाई गई। चाहे वह भारत के किसी सुदूर अंचल से आया नाटक हो या फिर रूस, अमेरिका से। सभी में परफॉरमेंस या प्रस्तुति के स्तर को ही देखा गया। उसके बाद ही उन्हें चयनित किया गया’।

थियेटर के विदेशी समूह और संस्थाएं भी साथः त्रिपाठी ने कहा - ‘विदेशी नाट्य संस्थाओं और थियेटर एजुकेशन से जुड़े संस्थानों ने भी नाट्य विद्यालय के इस महोत्सव में अपने स्तर पर जुड़ने में ख़ासी रुचि दिखाई है। वे परफॉर्म करने के साथ ही खर्च भी वहन कर रहे हैं। पोलेंड से लेकर, मैड्रिट और मास्को तक परफॉरमेंस होंगे। हर महाद्वीप के कम से कम एक देश में नाट्य प्रस्तुति 25वें भारंगम का हिस्सा बनेंगी। इसमें इंडियन डायस्पोरा का महत्वपूर्ण योगदान है’।

महोत्सव में महिला निर्देशकों की भागीदारीः नाट्य विद्यालय के निदेशक ने कहा, महोत्सव में भगवान बिरसा मुंडा, लोकमाता अहिल्या बाई, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों और रतन थियम, दया प्रकाश सिन्हा, बंसी कौल तथा आलोक चटर्जी जैसी थिएटर हस्तियों को याद किया जाएगा। इब्राहिम अलकाजी की जन्मशती पर उनके योगदान को लेकर एक विशेष सेमिनार आयोजित होगा। विविध संस्कृतियों के इस समागम में कई विशेष हस्तियां भी शामिल होंगी जो संवाद और संगीत कार्यक्रमों में भाग लेंगी।

श्रद्धांजलि और विशेष आयोजनः त्रिपाठी ने कहा, इस महोत्सव में हर तरह के रंगमंच को देखने का अवसर मिलेगा। इस बार आयोजन में वरिष्ठ नागरिकों, सेक्स वर्करों, ट्रांसजेंडर और विशेष बच्चों की भागीदारी भी हो रही है। संयोग से इस बार 33 महिला निर्देशकों, 19 विश्वविद्यालयों और 14 स्थानीय समूह भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कुल 277 प्रस्तुतियों में 228 भाषाओं और बोलियों का समावेश भारंगम में होगा। श्रुति के तहत 17 नई पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा।

महाभारत समागम समापन

सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में हो महाभारत समागम का आयोजनः केंद्रीय मंत्री उइके

भोपाल। वीर भारत न्यास द्वारा भारत भवन में आयोजित सभ्यताओं के संघर्ष एवं औदार्य की महागाथा पर केंद्रित महाभारत समागम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए केन्द्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि महाभारत भारतीय सभ्यता का जीवंत ग्रंथ है, जिसमें जीवन, धर्म, नीति और मानवता के शाश्वत मूल्य समाहित हैं। सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की यह महागाथा हमें यह सिखाती है कि विविधता में एकता और संवाद ही किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने इच्छा जताई कि प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम निरंतर आयोजित होते रहें, ताकि समाज सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा रहे और अपनी विरासत को पहचाने।

इस अवसर पर वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने मंत्रीजी का महाभारत का मोमेंटो एवं न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक युगयुगीन भारतवंशी भेंट कर स्वागत किया। इसके साथ ही बहिरंग मंच पर भरत प्रभात निर्देशित अठ्ठारह दिन, पूर्व रंग मंच पर मयूरभंज छाऊ शैली में शुभश्री मुखर्जी द्वारा निर्देशित अभिमन्यु वध तथा अंतरंग सभागार में जापान से आये हिरोशी कोइके के निर्देशन में तैयार नाट्य प्रस्तुति महाभारत एवं अमृता लहरी द्वारा निर्देशित चित्रांगदा का मंचन किया गया।

महाभारत समागम एक साझा सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने का सफल प्रयासः श्रीराम तिवारी वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने महाभारत समागम के समापन समारोह में कहा कि सभ्यताओं के संघर्ष एवं औदार्य की महागाथा महाभारत के माध्यम से हमने यह अनुभव किया कि भारतीय परंपरा संवाद, सह-अस्तित्व और मानवीय मूल्यों की पक्षधर रही है। भारत भवन में आयोजित यह समागम देश और दुनिया के विविध कलाकारों, विचारकों और दर्शकों को एक साझा सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने का सफल प्रयास रहा।

महाभारत के महान आख्यान पर आधारित नृत्य-नाटिका अठारह दिन एक भव्य और प्रभावशाली मंचीय प्रस्तुति है, जो कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक युद्ध को केंद्र में रखती है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित इस महाकाव्य के अठारह दिवसीय महासमर को मानव इतिहास का पहला भीषण विश्व युद्ध माना जाता है। यह नृत्य-नाटक युद्ध की घटनाओं के साथ-साथ उसके पीछे छिपे षड्यंत्र, रणनीतियों और मानवीय द्वंद्वों को सशक्त रूप में प्रस्तुत करता है। 50 से अधिक कलाकारों और 20 से अधिक तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा सजी यह 90 मिनट की प्रस्तुति दर्शकों को भव्य दृश्यात्मक अनुभव के साथ भारतीय संस्कृति की आत्मा से जोड़ती है।

छाऊ नृत्य

महाभारत युद्ध के एक अत्यंत मार्मिक और वीर प्रसंग पर आधारित नृत्य-नाटिका अभिमन्यु वध युवा योद्धा अभिमन्यु की अद्भुत वीरता और बलिदान की कथा प्रस्तुत करती है। अर्जुन की लगातार जीत से विचलित कौरवों ने गुरु द्रोण के नेतृत्व में चक्रव्यूह की रचना की। इस जटिल युद्ध-रणनीति में फँसे अभिमन्यु ने अदम्य साहस के साथ कौरवों का सामना किया और वीरगति को प्राप्त हुए। नृत्य-प्रस्तुति का आरंभ श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों के आह्वान से होता है।

जापानी रंगमंच में महाभारत का समकालीन और मानवीय रूप हिरोशी कोइके ब्रिज कंपनी, जापान द्वारा प्रस्तुत और हिरोशी कोइके निर्देशित महाभारत की नाट्य प्रस्तुति ने दर्शकों को एक अनूठा अंतर-सांस्कृतिक अनुभव प्रदान किया। यह मंचन महाभारत को शक्ति, कर्तव्य, त्याग और मानवीय सीमाओं पर गहन विमर्श के रूप में प्रस्तुत करता है। ‘अष्टावक्र’ और ‘वत्सला हरण’ के मंचन के साथ हुआ कठपुतली महोत्सव समापन महाभारत समागम अंतर्गत आयोजित तीन दिवसीय कठपुतली समारोह के अंतिम दिन दो विशेष प्रस्तुतियों का मंचन किया गया। पहले सत्र में प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार अनुपमा होस्केरे के निर्देशन में ‘अष्टावक्र’ का मंचन हुआ, जबकि समापन प्रस्तुति ‘वत्सला हरण’ निर्देशक गणपत सखाराम मसागे द्वारा प्रस्तुत की गई। अनुपमा होस्केरे ने कहा कि वे पिछले 30 वर्षों से कठपुतली कला के माध्यम से समाज को महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथों के पाठ की ओर प्रेरित कर रही है।

विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी

- राष्ट्रपति बोलीं-बेटियों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर रिकॉर्ड बनाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। 77वां गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि ये उत्सव देशवासियों में राष्ट्रीय एकता तथा गौरव की भावना को मजबूत बनाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि

इस साल गणतंत्र दिवस के साथ-साथ वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने का उत्सव भी मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का यह पवित्र दिन हमें देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर सोचने और समझने का मौका देता है। समय के साथ हमारे देश की हालत बदली है। भारत आजाद हुआ और हम खुद अपने देश के भविष्य को तय करने वाले बने। उन्होंने कहा कि देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 57 करोड़ जन-धन अकाउंट में 56 फीसदी महिलाओं के अकाउंट हैं। 10 करोड़ से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। खेल-कूद में हमारी बेटियों ने रिकॉर्ड बनाए हैं। महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीता है। नारी शक्ति कानून से देश की महिलाएं और सशक्त होंगी।

जयशंकर ने अमरीकी नेताओं से की मुलाकात

- भारत-यूएस ट्रेड डील पर धीरे-धीरे आग बढ़ रही है बात

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत और अमेरिका के रिश्तों, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की स्थिति और यूक्रेन में चल रहे युद्ध जैसे बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। इस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में माइक रोजर्सएएल और

एडम स्मिथ जैसे सांसद शामिल थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस के साथ बातचीत हमेशा से भारत और अमेरिका के रिश्तों का एक अहम हिस्सा रही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस मुलाकात के बारे में एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, उन्होंने लिखा, अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ एक अच्छी बातचीत हुई, हमने भारत-अमेरिका संबंधों के विभिन्न पहलुओं और यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की।

गणतंत्र दिवस पर 982 जवानों को वीरता और सेवा पदक

- इनमें 125 वीरता पुरस्कार शामिल, जम्मू-कश्मीर पुलिस को सबसे ज्यादा 45 मेडल

नई दिल्ली (एजेंसी)। गणतंत्र दिवस 2026 पर केंद्र सरकार ने गैलेंट्री अवॉर्ड्स और सेवा मेडल की घोषणा की है। इस बार 982 पुलिस, फायर ब्रिगेड, होम गार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विस से जुड़ें कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। इन पुरस्कारों में 125 वीरता पदक (गैलेंट्री मेडल्स) भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा 45 वीरता पदक जम्मू और कश्मीर ऑपरेशन थिएटर में तैनात कर्मियों को दिए गए हैं। इसके बाद नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के 35 और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात 5 कर्मियों को दिए गए हैं। फायर ब्रिगेड सर्विस के 4 बचावकर्मी भी वीरता पदक विजेताओं में चुने गए हैं। 982 वीरता और सेवा मेडल में से 125 गैलेंट्री मेडल हैं।

पहली बार रुद्र हेलीकॉप्टर की पायलट बनी एक महिला ऑफीसर

- गणतंत्र दिवस समारोह में आज दुनिया देखेगी कैप्टन हंसजा शर्मा की उड़ान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की रक्षा सेनाओं और युद्ध भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। भारतीय सेना में कैप्टन हंसजा शर्मा रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में क्वालिफाई होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। 26 जनवरी पर दुनिया पहली बार एक महिला अधिकारी को रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते देखेगी। गणतंत्र दिवस पर इस बार कर्तव्य पथ पर महिलाओं के शौर्य की एक और गाथा लिखी जाएगी। भारतीय सेना में कैप्टन हंसजा शर्मा की उपलब्धि को आर्मी एविएशन कोर में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जाता है। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ध्रुव हेलीकॉप्टर का आर्म्ड वेरिएंट है। रुद्र को हमले और टोही मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। यह उन्नत निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणालियों से लैस है और इसमें हथियार लगाए जा सकते हैं, जिससे युद्ध क्षेत्र में यह हेलीकॉप्टर दमदार हथियार बन जाता है। कैप्टन हंसजा शर्मा ने भारत की पहली महिला रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाना सिर्फ उड़ान कौशल के बारे में नहीं है, बल्कि इसके लिए उच्च स्तर की परिचालन तत्परता, युद्ध के मैदान की जागरुकता

जरूरी है। होने पर और संवेदनशील समय में निर्णय लेना शामिल हो सकता है। कैप्टन हंसजा शर्मा की सफलता महिलाओं को शामिल करने के प्रति सेना के बदलते दृष्टिकोण को दर्शाती है,जिन्हें कभी पहुंच से बाहर माना जाता था।

एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र-सेना के 3 अफसरों को कीर्ति चक्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले रविवार को केंद्र सरकार ने गैलेंट्री

अवॉर्ड्स और सर्विस मेडल की घोषणा की। एस्ट्रोनॉट और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। वहीं तीन अधिकारियों को कीर्ति चक्र और 13 को शौर्य चक्र दिया जाएगा। इस बार पुलिस, फायर ब्रिगेड, होम गार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विस से जुड़े 982 कर्मियों को बेहतरीन (उत्कृष्ट) सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। इनमें 125 वीरता पदक (गैलेंट्री मेडल्स) भी शामिल हैं।

बीजेपी चीफ नितिन नवीन ने यूपी में फूंका चुनावी बिगुल

- मथुरा में कार्यकर्ताओं से कहा-कमर कस लीजिए, 2027 आ रहा
- कहा-यूपी में पहले बंदूक से सरकारें चलती थीं, अब विकास हो रहा

मथुरा (एजेंसी)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने यूपी में 2027 का चुनावी बिगुल फूंक दिया। उन्होंने रविवार को कार्यकर्ताओं से कहा- कमर कस लीजिए, 2027 आ रहा है। देश में ऐसी ताकतें भी हैं, जो देश को काटने, बांटने में विश्वास करती हैं। ऐसी ताकतें चुनाव के समय ही जीवित होती हैं। उनसे भी लड़ना है। उन्होंने कहा- ऐसे लोग भी घूम रहे हैं, जिन्होंने संविधान को तार-तार किया, जिन्होंने यूपी के विकास को धता बताते हुए केवल अराजक लोगों को आगे बढ़ाया। हम भूले नहीं हैं कि बंदूक की नोक पर भी यूपी की सरकार चलती थी, लेकिन आज यूपी की सरकार जनता के वोट से चल रही है।

नितिन नवीन ने कहा-यूपी जिस तरह विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। जो लोग राजनीति को टाइम पास समझते हैं। चुनाव आता है तो आते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ रहा है। दरअसल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार मथुरा पहुंचे थे।

कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। बुलडोजर से फूल बरसाए। नितिन नवीन ने मंच से गदा लहराई। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। वृंदावन के छटीकरा रोड पर अक्षयपात्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की मन की बात सुनी। बांके बिहारी मंदिर में पूजा-अर्चना की। इससे पहले सीएम योगी ने नितिन नवीन का स्वागत किया। भाजपा की जीत के लिए कार्यकर्ताओं से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की अपील की। नितिन नवीन के साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत संगठन के तमाम नेता भी मौजूद रहे।

पहले भाषण में युवाओं को साधने की कोशिश- नितिन नवीन ने अपने पहले भाषण में युवाओं को साधने की कोशिश की। कहा कि युवाओं को सक्रिय राजनीति में आगे आना चाहिए। पीएम मोदी भी कहते हैं कि हम एक कदम चलेंगे तो देश 140 करोड़ कदम चलकर विकास की पटरी पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने सभी युवाओं से युवाओं से यूपी को विकसित बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का भी आग्रह किया। उन्होंने यूपी के पहले दौरे में ही सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कहा कि आज देश का हर राज्य विकसित राज्य बनकर उभर रहा है। यूपी उसका नेतृत्व कर रहा है।

सोशल मीडिया पर हथियारों की डील एसटीएफ ने दो आरोपियों को पकड़ा

5 पिस्टल जब्त, एक आरोपी फरार, इंस्टाग्राम-फेसबुक पर सौदेबाजी

इंदौर। स्पेशल टास्क फॉर्स (एसटीएफ) ने सोशल मीडिया के जरिए अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े आरोपियों के नाम पवन और राजू बताए गए हैं, जबकि हेप्पी नामक सिकलीगर मौके से फरार हो गया। खंडवा जिले के सिंगनूर क्षेत्र के सिकलीगरों के हथियार लेकर आने की सूचना पर एसटीएफ निरीक्षक रमेश चौहान के नेतृत्व में टीम ने पदमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदौर-खंडवा रोड पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पकड़े गए आरोपियों के नाम पवन और राजू बताए गए हैं, जबकि हेप्पी नामक सिकलीगर मौके से फरार हो गया। दोनों खरगोन के गोराड़िया गांव के बताए जा रहे हैं। वहीं उनसे कुछ दूर पीछे आ रहा मुख्य आरोपी

हैप्पी सिकलीगर निवासी संग्राम फरार हो गया। चौंकाने वाली बात ये है कि अब तक देसी कट्टों के लिए बदनाम सिकलीगरों के पास पहली बार फैक्ट्री मेड जैसी पिस्टल मिली हैं, जिनमें आधुनिक लॉक सिस्टम लगाए गए हैं। डीएसपी राजेश सिंह चौहान के अनुसार आरोपियों के पास से पांच पिस्टल बरामद की गई हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों के दिल्ली, राजस्थान,उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों के बदमाशों से संपर्क हैं। आरोपी इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से ही हथियारों की डील तय करते थे। यूपी व हरियाणा में हथियारों की सप्लाई जब्त पांचों पिस्टल का वजन काफी ज्यादा है। आगे नली और लॉक सिस्टम भी फैक्ट्री मेड पिस्टल जैसा है। पुलिस ने बताया कि यह पिस्टल कैसे बनाई गई, इसकी जांच जारी है।

आरोपी सोशल मीडिया के जरिए तस्करों व खरीदारों से संपर्क कर यूपी व हरियाणा में सप्लाई करते हैं। पुलिस के मुताबिक जब्त हथियार उन्नत किस्म के हैं और देखने में विदेशी हथियारों जैसे प्रतीत होते हैं। इसी कारण आरोपियों ने हथियारों की कीमत 20 से 25 हजार रुपये प्रति पीस तय कर रखी थी। फरार आरोपी हेप्पी की गिरफ्तारी के बाद इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद है।

इंदौर में दिन का पारा 4,5 डिग्री उतरा पहाड़ों से चली सर्द हवाओं ने ठिठुराया

पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का प्रभाव इंदौर पर देखने को मिल रहा

इंदौर। पश्चिमी विक्षोभ के चलते वसंत पंचमी के दूसरे दिन से मौसम में फिर बदलाव आया। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। उत्तराखंड के चारों धाम और मसूरी में भारी बर्फबारी से इंदौर में भी सर्द हवाओं का असर हुआ। शनिवार को दिन का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसमें शुक्रवार के मुकाबले साढ़े चार डिग्री की गिरावट आई। शुक्रवार को वसंत पंचमी पर इंदौर का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य था। लेकिन, शनिवार को दिन का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम था। एक दिन में अधिकतम

तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की तेज गिरावट दर्ज हुई।

रात के पारे में बदलाव- वसंत के आगमन के साथ ही मौसम में परिवर्तन आरंभ हो जाता है। 22 जनवरी को न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा और दिन में गर्मी का एहसास होने था। लेकिन, दूसरे ही दिन मौसम ने एकदम करवट बदली और शहर को ठंडी हवाओं ने जकड़ लिया। शनिवार को सुबह तेज ठंडी हवाओं के साथ शीतलहर महसूस की गई। शुक्रवार रात से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चली थी। शनिवार को दिन भर धूप के तेवर भी ठंडे रहे। हालांकि, हवा की रफ्तार घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। ठंडी हवाओं के कारण मौसम में आर्द्रता 64 प्रतिशत दर्ज की गई। ठंड से बचने के लिए लोग दिनभर गर्म कपड़ों में नजर आए।

उत्तरी हुआ, हवा का रुख

मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का प्रभाव इंदौर पर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से हवाओं का रुख दक्षिण का था, इस कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन बर्फबारी के कारण हवाओं का रुख उत्तर की ओर हो गया। इससे तापमान में गिरावट आई है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। बर्फबारी और ठंडी हवाओं के कारण ठंड का दौर एक दो दिन जारी रहेगा।

फर्जी शिकायतों का आरोप, एफआईआर की मांग

इंदौर। मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया में फर्जी शिकायतों का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। युवक कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के दौरान फर्जी शिकायतों का अंबार लगाया जा रहा है, जिससे कांग्रेस के वोट बैंक को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। युवक कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता शनिवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर प्रमाण सहित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि एक ही शिकायतकर्ता द्वारा 70 से अधिक आपत्तियां लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष एवं विधानसभा क्षेत्र-3 के नेता दानिश खान के नाम पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है,जबकि उनका परिवार तीन पीढ़ियों से इंदौर में निवासरत है और उनके पिता राज्यसभा के प्रतिनिधि रह चुके हैं। युवक कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा से जुड़े लोग फर्जी शिकायतकर्ता बनकर मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित करने की साजिश कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने जिला निर्वाचन अधिकारी से फर्जी शिकायतकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

तेज डीजे बजाने पर पुलिस की कार्रवाई

इंदौर। आमजन की सुविधा और शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना तिलक नगर पुलिस ने अवैध रूप से तेज आवाज में डीजे संचालन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार निर्धारित समय के बाद डीजे बजाने एवं ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एसेंशियल होटल के गार्डन में बिना अनुमति और तय ध्वनि मानकों से अधिक आवाज में डीजे संचालन पकड़ा। मौके पर दुर्गेश साउंड के डीजे संचालक मुकेश सोनी एवं अक्षत के खिलाफ थाना तिलक नगर में अपराध क्रमांक 31/26 के तहत धारा 15(1) म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं 223(ए) बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 12 डीजे साउंड, 2 एम्प्लीफायर, 13 एक्सटेंशन कार्ड, 3 एक्सटेंशन बोर्ड, 2 पावर बोर्ड और 2 बफर जब्त किए।

आयुक्त ने निरीक्षण किया, गुणवत्ता पर जोर दिया

इंदौर। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने शनिवार को चंदन नगर से एयरपोर्ट रोड तक प्रमुख सड़कों का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण की शुरुआत तीन इमली चौराहे के समीप निर्मित 3आर सेंटर से की गई। इसके बाद आयुक्त ने तीन इमली चौराहे पर निर्माणाधीन सर्विस रोड और ड्रेनेज लाइन कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं तथा निर्माण उपरांत रेस्टोरेशन कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ किया जाए। इसके पश्चात चंदन नगर चौराहा से कॉलोनी नगर होते हुए एयरपोर्ट रोड तक प्रस्तावित सड़क निर्माण का निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने सड़क की लंबाई, चौड़ाई, लागत एवं चौड़ीकरण में आने वाली बाधाओं की जानकारी ली और तकनीकी परीक्षण व विभागीय समन्वय के साथ कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके।

सड़क निर्माण में खोदे गए गड्ढे में गिरी युवती

राहगीरों ने निकाला, सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेड्स लगाए

इंदौर (नप्र)। इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में शनिवार रात एक युवती स्कूटर सहित सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद वह काफी देर तक वहीं बेसुध पड़ी रही। राहगीरों की

नजर पड़ने पर उसे बाहर निकाला गया, जबकि बाद में स्कूटर को भी गड्ढे से बाहर निकाला गया। घटना स्कीम नंबर-51 स्थित कचरा स्टेशन के पास की है। बताया जा रहा है कि युवती स्कूटर से गुजर रही थी, तभी संतुलन बिगड़ने से वह सीधे गड्ढे में गिर गई। यह गड्ढा सड़क निर्माण के दौरान ड्रेनेज लाइन डालने के लिए खोदा गया था, जिसे ठीक से बंद नहीं किया गया। घायल युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर रात में पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेड्स लगाए गए। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि इलाके में भारी अंधेरा रहता है और सड़क निर्माण के कारण मार्ग काफी संकरा हो गया है। इसी वजह से यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं। रहवासियों ने रात में अधिकारियों को भी फोन लगाए, लेकिन कोई जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा।

किराये की कारों से करोड़ों की ठगी जालसाज पुलिस के चंगुल में फंसा

3 करोड़ की 24 लग्जरी कारें जब्त, 40 से अधिक फरियादी सामने

इंदौर। किराये की कार लेकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर आरोपी को अन्नपूर्णा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी संजय कालरा लोगों से महंगी कारें किराए पर लेता था और बाद में उन्हें अलग-अलग जगह गिरवी रखकर मोटी रकम हासिल कर लेता था। इस फर्जीवाड़े में उसने करोड़ों रुपये की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार, पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक फरियादी ने अन्नपूर्णा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी ने उसकी कार किराए पर ली थी और शुरुआती दो महीने किराया देने के बाद भुगतान बंद कर दिया। शिकायत दर्ज होते ही एक-एक कर कई अन्य पीड़ित सामने आने लगे। देखते ही देखते थाने पर आरोपी संजय कालरा के खिलाफ करीब 40 आवेदन पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने इंदौर के साथ-साथ आसपास के जिलों में भी इसी तरह की धोखाधड़ी करना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने अब तक 3 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 24 लग्जरी कारें बरामद की हैं।

डीसीपी आनंद कलादगी ने बताया कि आरोपी से अभी पूछताछ जारी है और जांच में सामने आया है कि करीब 16 और कारें बरामद होना बाकी हैं। आरोपी किराए पर ली गई गाड़ियों को बिना मालिक की जानकारी के गिरवी रख देता था। पुलिस को उम्मीद है कि आगे की पूछताछ में इस बड़े कार ठगी नेटवर्क से जुड़े और भी अहम खुलासे हो सकते हैं।

पुलिसकर्मियों के नाम से धमकी

बताया गया कि संजय हमेशा पुलिस कंट्रोल रूम आता-जाता था। कई पुलिस अधिकारियों से उसके संबंध हैं। क्राइम ब्रांच और कई थानों के खुफिया पुलिसकर्मियों से भी दोस्ती बताई जा रही। जब कोई पीड़ित उससे अपनी कार वापस मांगता, तो वह पुलिसकर्मियों का रौब दिखाकर उन्हें धमकाता था। उसके मोबाइल फोन में कई पुलिसकर्मियों के साथ वॉट्सऐप चैटिंग भी मिली। इस कारण सालों तक पीड़ितों की थाने में सुनवाई नहीं हो पाती थी, हालांकि अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। लेकिन, इसके कई प्रमाण सामने आए हैं।

सांसद के अंगरक्षक के फायरिंग प्रयास पर पुलिस एक्शन संदिग्ध

गंभीर धाराओं से बचाने के लिए सुरक्षा गार्ड थाने पर डटे रहे

इंदौर। एमजी रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत लोखंडे पुल के पास सांसद के अंगरक्षक द्वारा शराब के नशे में पिस्टल तानकर फायरिंग के प्रयास का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी अविनाश भदौरिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया, लेकिन लगाए गए धाराओं को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद देर रात तक एमजी रोड थाने पर हलचल बनी रही। जानकारी के अनुसार आरोपी अविनाश भदौरिया को गंभीर धाराओं से बचाने के लिए अलग-अलग स्थानों पर पदस्थ पुलिस सुरक्षा गार्ड बड़ी संख्या में थाने पर डटे रहे।

इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी फोन कॉल्स लगातार चलते रहे, जिससे दबाव की स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज कराने को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पर अड़े रहे। इस दौरान एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा, एसीपी विनोद दीक्षित और एमजी रोड थाना प्रभारी टीआई विजय सिसोदिया लंबे समय तक मौके पर मौजूद रहे और बजरंग दल कार्यकर्ताओं को समझाइश देते रहे कि मामला दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर धैर्य रखा जाए। हालांकि, कार्यकर्ता एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अडिग रहे और अंततः कई घंटे बाद फरियादी विशाल काले, सुनील जोशी, अनुज गोड, मनोज गोड, देवांश डहाके और जतीन वर्मा की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की सामान्य धाराएँ लगाए जाने को लेकर असंतोष बना हुआ है। इस बीच अब यह मामला राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया है।

कांग्रेस प्रवक्ता की प्रतिक्रिया

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमित चौरसिया ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सांसद के अंगरक्षक द्वारा शराब के नशे में पिस्टल तानकर फायरिंग का प्रयास किया जाना गंभीर अपराध है। इसके बावजूद पुलिस ने मामले में केवल सामान्य धाराएँ लगाकर गंभीर अपराध को हल्का करने का प्रयास किया है। ट्वीट में आरोप लगाया कि यदि आरोपी कोई आम नागरिक होता तो उस पर हत्या के प्रयास जैसी कठोर धाराएँ स्वतः लगाई जातीं, लेकिन वर्दीधारी और प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा होने के कारण कानून के अलग मापदंड अपनाए गए।

महू के सिमरोल में 7 किमी लगा था लंबा जाम

नर्मदा जयंती पर ओंकारेश्वर जा रहे श्रद्धालु फंसे

महू (नप्र)। महू के पास सिमरोल थाना क्षेत्र में रविवार सुबह यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। तलाई नाके से लेकर भेरू घाट के आगे तक करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दरअसल, नर्मदा जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु ओंकारेश्वर की ओर जा रहे थे, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

वाहनों की लंबी कतारें लगी

स्थानीय लोगों और राहगीरों के अनुसार, सुबह से ही वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती गई। हालांकि, यातायात नियंत्रण के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण जाम की स्थिति विकराल हो गई। कार, बस, बाइक और भारी वाहनों की लंबी कतारों में कई यात्री घंटों तक फंसे रहे।

जाम खुलवाने पुलिस पहुँची – मौके पर मौजूद पुलिस बल जाम को खुलवाने का लगातार प्रयास करता रहा। लेकिन, श्रद्धालुओं की अत्यधिक संख्या के चलते यातायात सुचारू नहीं हो सका।

एमपीपीएससी के खिलाफ आंदोलन

इंटरव्यू अंकों में कटौती की मांग, 13 महीने बाद फिर शुरू हुआ धरना प्रदर्शन

इंदौर (नप्र)। इंदौर में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) के सामने अभ्यर्थियों ने एक बार फिर शनिवार देर रात से आंदोलन शुरू कर दिया है। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के नेतृत्व में आयोग कार्यालय के बाहर धरना दिया जा रहा है। 10 सूत्री मांगों को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अगले चार दिन तक जारी रहेगा। धरने में कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। अभ्यर्थियों ने आयोग परिसर के बाहर ही बिस्तर बिछा लिए हैं। अलाव जलाकर रात वहीं बिताई जा रही है। इस आंदोलन को अभ्यर्थियों ने 'न्याय यात्रा 2.0' नाम दिया है। दरअसल, ठीक 13 महीने पहले दिसंबर 2024 में भी सैकड़ों पीएससी अभ्यर्थियों ने इसी तरह का आंदोलन किया था, जो करीब एक सप्ताह तक चला था, तब जिला प्रशासन ने कई मांगें मानने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया था, लेकिन

अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन वादों में से अधिकांश आज तक पूरे नहीं हुए।

हाईकोर्ट से मंजूरी के बाद धरना

एनईवाययू के संयोजक राधे जाट ने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर एनईवाययू की न्याय यात्रा 2.0 को हाईकोर्ट इंदौर से मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी डब्ल्यूपी-3025-2026 में आर्टीकल 19 के तहत दी गई है। यात्रा 10 सूत्रीय मांगों के लिए निकाली जा रही है। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और अन्य स्टूडेंट शांति पूर्वक आंदोलन में शामिल होंगे। हमें कोर्ट से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अनुमति मिली है, इसलिए हम पूरी शांति से यहां धरना देंगे।

इंटरव्यू अंकों में कटौती

अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी मांग स्टेट सर्विस परीक्षा के इंटरव्यू अंकों को लेकर है। उनका कहना है कि 185 अंकों का इंटरव्यू अत्यधिक है, इससे चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका रहती है। इसे घटाकर 100 अंक किया जाए।

पिछली मांगें अधूरी, नाराजगी बरकरार

पिछले आंदोलन के दौरान जिन 6-7 मांगों को मानने की बात कही गई थी, उनमें से केवल दो ही लागू हो सकीं। अधिक पदों पर भर्ती का वादा पूरा नहीं हो सका। अभ्यर्थियों का कहना है कि करीब 90 प्रतिशत मांगें आज भी लंबित हैं।

जब तक मांगे नहीं मानी धरना जारी रहेगा

छात्र अभिषेक जाट ने कहा कि हम पिछले दो-तीन वर्षों से लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एमपीपीएससी हर साल पदों की संख्या घटाता जा रहा है। इसी के विरोध में अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आयोग मांगें नहीं मानता, तब तक धरना जारी रहेगा। आंदोलन के कारण पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अभिषेक ने बताया कि पिछले आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को पद बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद पिछले वर्ष केवल 158 और इस बार 156 पद ही घोषित किए गए।

नजरिया

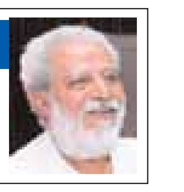

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

वंदे मातरम् पर विवाद क्यों?

देश में प्रतिवर्ष हजारों-लाखों लोग जहरीली हवा, पानी, जहरीले अन्न से मरने को लाचार हैं इस पर संसद में चर्चा होती। प्रदूषण कितना बड़ा संकट हो चुका है जिसने देश की राजधानी दिल्ली एवं महानगरों को चपेट में ले लिया। बल्कि दिल्ली का हर आदमी साँस से संबंधित बीमारियों से त्रस्त है। छोटे-छोटे बच्चे अस्थमा के शिकार हो रहे हैं, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद चर्चा नहीं करती। परंतु जब सभी दलों के लिये सांप्रदायिकता से ही वोट की तिजोरी भरना है तो इनकी चर्चा कौन करेगा? महाराष्ट्र में हिंदी वासियों को पीटा और मारा जा रहा है। अर्णव खैरे जैसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्या भारत में हिंदी बोलना अपराध हो गया? इन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए। यह कैसा राष्ट्रवाद या भारतीयता है कि आजादी के 78 वर्षों के बाद भी हम अंग्रेजी पढ़ने-बोलने को विवश किये जाते हैं। हिंदी और हिंदी वासियों पर हमला किया जाता है और इन विषयों पर संसद में कोई चर्चा नहीं होती। भाजपा हिंदी, हिंदु हिंदुस्तान के सवाल पर मुंह बंद कर लेती है।

संसद का 10 घंटे का विशेष सत्र जो वन्दे मातरम् गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर, प्रधानमंत्री की पहल पर बुलाया गया था और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसमें बहस की शुरूआत की थी। 10 घंटे की संसद की बहस से देश को क्या हासिल हुआ सिवाय इसके कि परस्पर गाली-गलौज होती रही। गृहमंत्री श्री अमित शाह ने संसद और विधानसभाओं का रिकॉर्ड निकालकर वह सूची जारी की है जिन लोगों ने संसद और विधानसभाओं में वन्दे मातरम् नहीं गाया था। जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मुझे वन्दे मातरम् गाने में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता। गीत की पंक्तियों में भी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं है, परंतु मौलाना मदनी ने इस सुस्त बहस को यह कहकर कि वन्दे मातरम् गाना इस्लाम के खिलाफ है, सुस्त बहस को जिंदा कर दिया और वन्दे मातरम् गाने को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। अगर हिन्दुस्तान की संसद और विधानसभाओं में सांसदों व विधायकों की संख्या लगभग 6 हजार के आसपास है, उनमें से अगर दो चार लोगों ने वन्दे मातरम् नहीं गाया तो उसमें समूचे देश को क्या असर पड़ता है। यह एक मामूली सी बात है तथा एक निरर्थक बहस है, परंतु मदनी साहब ने उसे व्यर्थ में तूल और हवा दी। कोई वन्दे मातरम् गाये न गाये यह उसका अपना अधिकार है, क्योंकि अभी तक वन्दे मातरम् गीत को गाने की कोई कानूनी अनिवार्यता भी नहीं है, जिस प्रकार जन-गण-मन राष्ट्रीय गीत को गाने कानून है, ऐसा वन्दे मातरम् को लेकर कोई कानून नहीं है। मौलाना मदनी का संबंध देवबंद के साथ है, जो एक पुरानी इस्लामिक संस्था है। जिसकी आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परंतु संस्था के वर्तमान मुखिया के द्वारा ऐसी अतार्किक बहस से देश और मुस्लिम समाज का कोई भला नहीं होता, बल्कि देश के आमजन के मानस में मुस्लिम भाईयों को अनजाने में शंकालू बना दिया जाता है।

वन्दे मातरम् गीत के बारे में कुरान या इस्लाम में कोई रोक नहीं है। क्योंकि जिस समय हजरत मोहम्मद साहब को कुरान की आयतें उतरी थी उस समय इस्लाम मानने वालों का क्षेत्र अलग था और उस समय वन्दे मातरम् गीत भी नहीं लिखा गया था। जब उर्दू को मादरे जवान बोलते हैं और वतन को मादरे वतन बोलते हैं तो इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ माता से नहीं है। मादरे शब्द का उद्गम फारसी शब्द यानि मां और अरबी शब्द वतन यानि देश से मिलकर बना है। जिसका अर्थ ही है कि जिस देश में या भूमि में व्यक्ति पैदा होता है उसके प्रति उसके मन में माँ के प्रति समान प्रेम तो होता है फिर माँ की वंदना में क्या आपत्ति हो सकती है? इसलिये बेवजह वन्दे मातरम् गीत को धर्म के साथ जोड़ना नितांत अनुचित है। कुछ फिरकापरस्त लोग सत्ता के मद में ऐसे नारे लगाते और गढ़ते हैं जिससे उन्हें राजनीतिक खुराक मिलती है। कुछ नासमझ लोग योजनाबद्ध ढंग से यह नारा लगाते हैं कि भारत देश में रहना है तो वन्दे मातरम् कहना है और ऐसे नारों से मुस्लिम भाईयों के साथ इनके उकसावे और मुस्लिम समाज के अतार्किक बहस के कारण हुए ध्रुवीकरण से देश में हिन्दु मतों से भाजपा की सरकार है। इन नारे लगाने वालों को सोचना चाहिये कि 2 से 3 करोड़ भारतीय दुनिया के अन्य देशों में भी रहते हैं, वहां की सरकारें या समाज उन्हें अमेरिकी ब्रिटिश या अन्य देशों के राष्ट्रगीत गाने को बाध्य नहीं करती। अपने वतन या मिटटी के प्रति प्रेम, जहां इंसान ने जन्म लिया है वह तो होना स्वाभाविक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1882 में आनंदमठ के दूसरे संस्करण प्रकाशित करते समय प्रस्तावना में लिखा था कि समस्त माता शब्द यह भारत के लिये लिखा गया है। पृष्ठ (4 और 5 पर) श्री अरविंदों ने 1907 में वन्दे मातरम् अखबार के 11 अप्रैल के अंक में इस गीत का समर्थन किया था। यह तथ्य है कि श्री अरविंदो आजादी के सेनानी थे और आंदोलन में जेल में रहे थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1917 में नेशनलिज्म पुस्तक में लिखा था कि बकिंम की माता बंगाल की नहीं संपूर्ण देश की मां हैं वह हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैली है। कांग्रेस के 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, 1905 के बनारस अधिवेशन, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की शुरुआत वन्दे मातरम् गीत से हुई थी। उस समय दादाभाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1915 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इसे सुना तो कहा कि यह गीत मेरी रगों में बस गया।

ब्रिटिश सरकार ने इस गीत को खतरा बताकर आर्थिक दंड के साथ-साथ 6 माह की सजा का प्रावधान किया था। संविधान सभा ने भी इस गीत का समर्थन किया और एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से इसे अपनाया। केरल में तो खालिद ने इसे मलयाली में गाया था। फिर भी मैं यह मानता हूँ कि इस गीत को गाना न गाना कोई संवैधानिक दायित्व नहीं, बल्कि व्यक्ति का अपना अधिकार है। यह देश में खड़ा किया गया निरर्थक विवाद है जिसने लोगों के मानसिक विभाजन को हवा दी। इससे केवल उन लोगों को ही लाभ होगा जिनकी जड़ों को हिंदू और मुसलमान की सांप्रदायिकता से खुराक मिलती है। हालांकि एक पक्ष यह भी है कि मदनी साहब इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, तब भी ऐसे मुद्दों का अंत नहीं होने वाला। ऐसे मुद्दे किसी न किसी रूप में खड़े किये जाते रहे हैं। मेरे अनेक मुस्लिम मित्र हैं जो खुद ही वन्दे मातरम् का नारा लगवाते हैं। वे सच्चे मुसलमान भी हैं, वे इस्लाम और कुरान की नसीहतों पर चलते और मानते हैं।

अब एक और नई बहस शुरू की गई है, प. बंगाल के एक विधायक श्री हुमायुं कबीर ने कहा है कि वे 1 लाख लोगों के साथ कुरान पाठ करेंगे। इसके पहले भाजपा के नेताओं ने कोलकाता में सार्वजनिक गीता पाठ की घोषणा की थी और कहा कि इसमे 5 लाख लोग शामिल होंगे। संभवतः इन चुनाव में इससे गीता बनाम कुरान चुनाव का मुद्दा बनेगी। मैं समझता हूँ कि किसी भी धार्मिक पाठ का पाठन सार्वजनिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत होना चाहिये। धार्मिक ग्रंथों और उनके उद्देश्य व्यक्ति को मर्यादित करने के लिये होते हैं न कि दिखाने के लिये। हजारों सालों से लोग अपने घरों में गीता का पाठ करते आये हैं, मुस्लिम कुरान पढ़ते आये हैं, ईसाई बाइबिल पढ़ते आये हैं परंतु इनका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया गया, जब उद्देश्य ही परस्पर समाज को घृणा में बांटकर वोट लेना हो तब ऐसे सब नाटक किये जाते हैं। कुरान के ऐसे सार्वजनिक पाठ के बारे में तो हजरत मोहम्मद साहब ने भी नहीं कहा, मस्जिद में भी केवल नमाज सामूहिक तौर पर अदा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। उसे सारी पांडव सेना को सार्वजनिक रूप से नहीं पढ़ाया था। लोग गीता-कुरान के पाठ का प्रयोग अपने स्वार्थपूर्ति के लिये कर रहे हैं। इसे किसी भी मजहबी आधार पर तार्किक सिद्ध नहीं किया जा सकता। मैं नहीं चाहता कि सरकारें इन पर रोक लगाकर सांप्रदायिक सोच को फैलने का अवसर दें। बल्कि मैं चाहता हूँ कि हिन्दू मुस्लिम समाज ही ऐसी प्रतिक्रिया करे कि ऐसे आयोजन उचित नहीं हैं और वह ऐसे आयोजन में शामिल नहीं होंगे।

वैसे तो ममता बनर्जी ने हुमायुं कबीर को अपनी पार्टी से निकाल दिया है और कबीर ने भी अपनी अलग पार्टी बनाने की घोषणा की है, तथा ममता बनर्जी को चुनाव में हराने की भी घोषणा की है। इस घटना को भी कुछ लोग प्रायोजित मान रहे हैं और कुछ लोग तथ्यात्मक। इस बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी मेरे पास नहीं है पर मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि इन सबका परिणाम देश में मानसिक और मजहबी विभाजन के रूप में आयेगा। जिसका लाभ अन्ततः इन जमातों को ही मिलेगा जो हिन्दू या मुस्लिम के नाम से वोट लेकर अपनी सत्ता को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कितना अच्छा होता कि संसद इस 10 घंटे का इस्तेमाल देश और दुनिया की समस्याओं, महंगाई-बेरोजगारी, सीमा की समस्या, सुरक्षा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा पर भारत ने क्या पाया, इस पर चर्चा करती तो सार्थक होता।

देश में प्रतिवर्ष हजारों लाखों लोग जहरीली हवा, पानी, जहरीले अन्न से मरने को लाचार है इस पर संसद में चर्चा होती। प्रदूषण कितना बड़ा संकट हो चुका है जिसने देश की राजधानी दिल्ली एवं महानगरों को चपेट में ले लिया। बल्कि दिल्ली का हर आदमी साँस से संबंधित बीमारियों से त्रस्त है। छोटे-छोटे बच्चे अस्थमा के शिकार हो रहे हैं, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद चर्चा नहीं करती। परंतु जब सभी दलों के लिये सांप्रदायिकता से ही वोट की तिजोरी भरना है तो इनकी चर्चा कौन करेगा? महाराष्ट्र में हिंदीवासियों को पीटा और मारा जा रहा है। अर्णव खैरे जैसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्या भारत में हिंदी बोलना अपराध हो गया? इन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए। यह कैसा राष्ट्रवाद या भारतीयता है कि आजादी के 78 वर्षों के बाद भी हम अंग्रेजी पढ़ने-बोलने को विवश किये जाते हैं। हिंदी और हिंदी वासियों पर हमला किया जाता है और इन विषयों पर संसद में कोई चर्चा नहीं होती। भाजपा हिंदी, हिंदु हिंदुस्तान, के सवाल पर मुंह बंद कर लेती है।

कांग्रेस आजादी के आंदोलन की भावनाओं और महात्मा गांधी के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की भावना तथा प्रयासों की चर्चा नहीं करती है। यह कैसी भारतीय संसद है जो कि विदेशी जवान और साम्राज्यवादी प्रतीकों का तो समर्थन करने को तैयार है परंतु अपने देश की मातृभाषा को स्वीकारने या बचाने को तैयार नहीं है।

दुर्भाग्य है कि संसद के सभी दल सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता और संकीर्णता के आधार पर वोट पाते हैं तथा उसी की खुराक पर जिंदा हैं, अब इस पर देश की जनता को सोचना होगा।

भारतीय संविधान

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

लेखक स्वतंत्र टिपणीकार हैं।

स्वतंत्रता के स्वप्न से समकालीन चुनौतियों तक

भारतीय संविधान किसी राष्ट्र का साधारण विधि-ग्रंथ नहीं, बल्कि एक सभ्यता की चेतना, संघर्षों की स्मृति और भविष्य के स्वप्नों का सजीव दस्तावेज़ है। यह उस ऐतिहासिक क्षण की गवाही देता है जब सदियों की पराधीनता से मुक्त होकर भारत ने स्वयं को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण राष्ट्र के रूप में गढ़ने का संकल्प लिया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान केवल शासन की व्यवस्था तय करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने करोड़ों भारतीयों को गरिमा, समानता और स्वतंत्रता का भरोसा दिया। विविधताओं से भरे इस देश में भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति की बहुलता को एक सूत्र में पिरोना आसान नहीं था, किंतु संविधान ने इस असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव बनाया।

पचहत्तर वर्षों से अधिक की इसकी यात्रा भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल की साक्षी रही है। इस दौरान संविधान ने समय की कसौटी पर स्वयं को बार-बार परखा, संशोधनों और न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से स्वयं को नया रूप दिया, और बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढलता रहा। आज, जब लोकतंत्र, संस्थागत संतुलन और नागरिक अधिकारों पर नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तब संविधान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। संविधान ने न केवल शासन की संरचना तय की, बल्कि एक विविधतापूर्ण समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम भी किया। समय के साथ इसमें संशोधन हुए, व्याख्याएँ बदलीं और नई चुनौतियों के अनुरूप इसे ढालने का प्रयास किया गया, परंतु इसकी मूल भावना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। संविधान की रचना अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। संविधान सभा में देश के विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों, भाषाओं और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व था। डॉ. भीमराव आंबेडकर के नेतृत्व में बनी प्रारूप समिति ने दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन कर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप एक संतुलित ढाँचा तैयार किया। इस प्रक्रिया में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को केंद्र में रखा गया। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता की नींव रखना भी था, ताकि सदियों से वंचित वर्गों को न्याय मिल सके।

मौलिक अधिकार संविधान का हृदय कहे जाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे अधिकारों ने नागरिकों को राज्य की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान की। इन अधिकारों ने भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखा और नागरिकों को अपने विचार रखने, विरोध करने और न्याय पाने का अवसर दिया। समय-समय पर न्यायपालिका ने इन अधिकारों की व्याख्या कर उन्हें और व्यापक बनाया, जैसे जीवन के अधिकार में गरिमा, निजता और स्वच्छ पर्यावरण को शामिल करना। मौलिक कर्तव्यों का समावेश संविधान की नैतिक दृष्टि को दर्शाता है। अधिकारों के साथ कर्तव्यों की बात यह स्मरण कराती है कि लोकतंत्र केवल मांगों से नहीं चलता, बल्कि जिम्मेदार नागरिकता से सशक्त होता है। संविधान नागरिकों से राष्ट्र की एकता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण की रक्षा की अपेक्षा करता है। आज के समय में जब व्यक्तिगत स्वार्थ सामूहिक हितों पर हावी होता दिखता है, तब मौलिक कर्तव्यों की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। संघीय ढाँचा भारतीय संविधान की एक विशिष्ट विशेषता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन देश की विविधता को सम्मान देता है। यह व्यवस्था एक ओर राष्ट्रीय एकता बनाए रखती है, तो दूसरी ओर क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी स्थान देती है। हालांकि, समय के साथ केंद्र और राज्यों के संबंधों में तनाव भी देखने को मिला है। आर्थिक संसाधनों के बंटवारे, प्रशासनिक अधिकारों और राजनीतिक मतभेदों ने संघीय संतुलन को कई बार चुनौती दी है।

न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्र और सशक्त न्यायपालिका ने मूल संरचना सिद्धांत के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि संविधान की बुनियादी आत्मा से समझौता न हो। कई ऐतिहासिक फैसलों ने नागरिक अधिकारों को मजबूती दी और कार्यपालिका व विधायिका पर संवैधानिक अंकुश लगाया। फिर भी, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के बीच संतुलन बनाए रखना आज एक गंभीर विमर्श का विषय है। संविधान की 75+ वर्षों की यात्रा में संशोधनों की भूमिका भी अहम रही है। सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के साथ संविधान में लचीलापन लाने के लिए संशोधन किए गए। भूमि सुधार, पंचायती राज, शिक्षा का अधिकार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण जैसे प्रावधान समाज को अधिक समावेशी बनाने के प्रयास हैं। हालांकि, कुछ संशोधनों पर यह आरोप भी लगे कि वे राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित थे, जिससे संविधान की मूल भावना को ठेस पहुँची।

आज भारतीय संविधान कई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है। असहमति को देशद्रोह समझने की प्रवृत्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंध और संस्थाओं की स्वायत्तता पर सवाल लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। संविधान केवल किताबों में नहीं, बल्कि व्यवहार में जीवित रहना चाहिए, और इसके लिए राजनीतिक संस्कृति का संवैधानिक होना आवश्यक है। सामाजिक न्याय आज भी अधूरा सपना है। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। संविधान ने समानता का वादा किया, परंतु सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया है। महिलाओं की सुरक्षा और समान अवसर, आदिवासियों के अधिकार, और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे मुद्दे आज भी संवैधानिक आदर्शों की कसौटी पर समाज को परखते हैं।

डिजिटल युग ने भी संविधान के सामने नई चुनौतियाँ रखी हैं। निजता का अधिकार, डेटा सुरक्षा, सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की सीमाएँ और साइबर निगरानी जैसे प्रश्न आधुनिक लोकतंत्र के केंद्र में हैं। तकनीक जहाँ एक ओर नागरिकों को सशक्त बनाती है, वहीं दूसरी ओर राज्य की निगरानी क्षमता को भी बढ़ाती है। ऐसे में संविधान की व्याख्या को समय के साथ विकसित होना होगा। आर्थिक असमानता भी एक गंभीर संवैधानिक चुनौती है। संविधान ने सामाजिक और आर्थिक न्याय का सपना दिखाया, परंतु अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई इस आदर्श को कमजोर करती है। जब संसाधनों का असमान वितरण होता है, तो समान अवसर का सिद्धांत खोखला हो जाता है। एक सशक्त लोकतंत्र के लिए आर्थिक समावेशन अनिवार्य है।

भारतीय संविधान की 75+ वर्षों की यात्रा गौरव, संघर्ष और आत्ममंथन की कहानी है। यह दस्तावेज़ स्थिर नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया है, जो समय के साथ विकसित होता है। आज की चुनौतियाँ हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम संविधान के मूल्यों को केवल स्मरण करते हैं या उन्हें जीते भी हैं। संविधान की रक्षा केवल न्यायालयों या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। जब तक भारत का नागरिक संविधान को अपनी आस्था और आचरण का आधार बनाए रखेगा, तब तक यह महान दस्तावेज़ आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा देता रहेगा।

देशभक्ति

अदिति सिंह भदौरिया

लेखक स्तंभकार हैं

एक दिन का उत्सव या जीवन का संस्कार?

26 जनवरी—भारत के लिए केवल एक तारीख नहीं, बल्कि हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान और लोकतांत्रिक पहचान का प्रतीक है। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ, जिसने हमें अधिकार दिए, समानता का भरोसा दिया और एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में जीने का साहस दिया। हर वर्ष इस दिन तिरंगा लहराया जाता है, परेड होती है, देशभक्ति के गीत गूंजते हैं और हम गर्व से कहते हैं- 'हमें अपने देश पर गर्व है।'

लेकिन क्या यह गर्व सच में हमारे जीवन का हिस्सा है, या केवल एक दिन का औपचारिक प्रदर्शन?

26 जनवरी को हम तिरंगे को माथे से लगाते हैं, लेकिन 27 जनवरी की सुबह वही तिरंगा सड़कों पर पड़ा मिलता है- कचरे में, नालियों के पास, पैरों तले कुचला हुआ। प्रश्न यह नहीं है कि 26 जनवरी को हमने क्या किया, प्रश्न यह है कि 27 जनवरी को हम क्या सहन कर रहे हैं।

क्या हमें सड़कों पर पड़े फटे हुए तिरंगे नहीं दिखते?
क्या कचरे में पड़ा राष्ट्रध्वज हमारे भीतर कोई पीड़ा नहीं जगाता?
अगर नहीं, तो फिर हमारी देशभक्ति कितनी गहरी है?
तिरंगा केवल तीन रंगों का कपड़ा नहीं है।
केसरिया- त्याग और बलिदान का प्रतीक है,
सफेद- शांति और सच्चाई का,
और हरा- आशा और समृद्धि का।
बीच में स्थित अशोक चक्र हमें निरंतर कर्तव्य और गति का संदेश देता है।
जब यही तिरंगा कचरे में पड़ा होता है, तो क्या वास्तव में कपड़े का अपमान होता है, या हमारे मूल्यों का?
यह प्रश्न हमें खुद से पूछना होगा।
आज हमारी देशभक्ति तारीखों की मोहताज हो गई है—
15 अगस्त, 26 जनवरी, और शायद किसी क्रिकेट मैच के दौरान।
इसके अलावा तिरंगा हमारे जीवन से गायब रहता है।
हम बड़े गर्व से कहते हैं-
'हम भारतीय हैं।'
लेकिन क्या हम यह भी कहते हैं-
'हम जिम्मेदार भारतीय हैं'?
देशभक्ति केवल नारे लगाने से नहीं आती।
देशभक्ति तब आती है जब हम राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना सीखते हैं,
जब हम यह समझते हैं कि तिरंगे को हाथ में लेने से पहले और छोड़ने के बाद भी हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती।
आज हम बच्चों को सिखाते हैं—
'तिरंगा लहराओ।'
लेकिन क्या हम उन्हें यह भी सिखाते हैं-
'तिरंगे को संभालकर रखो, उसे जमीन पर मत गिरने दो, उसका अपमान मत होने दो'?
अगर 27 जनवरी को सड़कों पर पड़े तिरंगे हमें नहीं चुभते,
तो शायद समस्या तिरंगे में नहीं, हमारी संवेदनाओं में है।
देशभक्ति कोई एक दिन का मेहमान नहीं होनी चाहिए।
वह हमारे जीवन का स्वभाव बननी चाहिए।
जैसे हम अपने घर को गंदा नहीं करते,
वैसे ही हमें अपने देश के प्रतीकों को भी अपमानित नहीं होने देना चाहिए।
यह स्वीकार करना कठिन है, लेकिन सच यही है कि
हम उत्सव मनाने में आगे हैं,
पर जिम्मेदारी निभाने में पीछे।
अगर हम सच में अपने देश से प्रेम करते हैं,
तो हमें यह भी सोचना होगा कि-
- क्या हमने उपयोग के बाद तिरंगे को सही तरीके से रखा?
- क्या हमने दूसरों को तिरंगे का अपमान करते देख चुप्पी साध ली?
- क्या हमने बच्चों को केवल जोश दिया, या संस्कार भी?
देशभक्ति का असली अर्थ यही है-
गलत को देखकर चुप न रहना,
और सही को अपनाकर उदाहरण बनना।
26 जनवरी पर गर्व करना आवश्यक है,
लेकिन 27 जनवरी पर शर्मिंदा होना उससे भी अधिक ज़रूरी है,
क्योंकि वही दिन हमें हमारी वास्तविकता दिखाता है।
आइए, यह संकल्प लें कि-
हमारी देशभक्ति केवल भाषणों में नहीं, व्यवहार में दिखेगी।
हम तिरंगे को केवल लहराएंगे नहीं, उसका सम्मान भी करेंगे।
और सबसे महत्वपूर्ण—
हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि देशभक्ति एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि जीवन भर का संस्कार है।
जब तक कचरे में पड़ा तिरंगा हमें भीतर से चोट नहीं पहुँचाता,
तब तक हमारी आज़ादी अधूरी है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा अग्निबाण पब्लिकेशन, 121, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त'

लेखक व्यंग्यकार हैं।

तहसील के भूत और गणतंत्र की धूप

शहर के उस 'घपला गंज' इलाके में, जहाँ गणतंत्र की जड़ें उतनी ही गहरी थीं जितनी कि सरकारी सड़क पर पड़ा हुआ गड्ढा, मुंशीराम 'मक्खन' गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे की रस्सी सुलझाने में ऐसे उलझे थे जैसे कोई नया दामाद ससुराल की मर्यादाओं में उलझता है। मुंशीराम, जिनका पेशा ही व्यवस्था की मलाई चाटना था, इस बार 'अमृत काल' के उत्साह में इतने डूबे थे कि उन्होंने खंभे पर पेंट करवाने के लिए उस पेंटर को बुलाया था जो चुनाव में विपक्षी पार्टियों के कालिख पोतने का विशेषज्ञ था। मुंशीराम ने चश्मा नाक पर टिकाते हुए कहा, देख भाई, कल झंडा फहराते वक्त अगर रस्सी अटकी, तो समझ लेना कि तुम्हारी देशभक्ति पर 'जीएसटी' लग जाएगा।

संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, पर झंडा फहराने का अधिकार केवल उसे है जिसकी फाइल मेज के ऊपर से चलती है। तभी वहां धर्मवीर 'धीठ' हाथ में हुक्का लिए प्रकट हुए। धर्मवीर ने आते ही झंडे के खंभे को लात मारते हुए उसकी मजबूती जांची, जैसे कोई डॉक्टर मरीज की नब्ज नहीं, बल्कि उसकी जेब की गहराई जांचता है। अरे मुंशी! तू यो झंडा फहरावेगा या प्रजातंत्र का कबाड़ा करेगा? यो खंभा तो कति ऐसा डगमगा रहा है जैसे अविश्वास प्रस्ताव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी। झंडा तो तू फहरा देगा, पर यो जो संविधान की किताब तूने मंच पै सजा रखी है, इसका क्या करेगा? इसे तो तूने पिछली बार टेंट वाले का हिसाब लिखने के लिए इस्तेमाल किया था। भाई, गणतंत्र दिवस तो केवल उन खातिर है जिनकी कोठियां ऊंची हैं, हम जैसे तो बस नीचे खड़े होकर बूंदी के लड्डू की आस में 'भारत माता की जय' बोलते रह जावें हैं। मुंशीराम ने एक गहरी सांस ली, जो देशभक्ति से कम और सरकारी बजट की चिंता से ज्यादा भरी थी, और बोले, 'धीठ भाई, ये उत्सव है, इसे तर्क की कसौटी पर मत कसो। यहाँ तो वो भी 'जन-गण-मन' गाता है जिसे 'जन' से नफरत और 'गण' से परहेज है।'

ठाकुर गजेंद्र सिंह 'घसीटा' ने जब मंच संभाला, तो उनके गले की खराश भी किसी राजकीय घोषणा जैसी सुनाई दे रही थी। उन्होंने चश्मा चढ़ाया और उस कागज को खोला जिस पर 'आजादी के मायने' लिखे थे, हालांकि वह कागज किसी पुरानी फाइल का पिछला हिस्सा लग रहा था जिस पर अभी भी 'बेदखली' के आदेश की गवाही बाकी थी। ठाकुर साहब बोले, भाइयों, आज हमारा देश स्वतंत्र है, हर नागरिक राजा है! धर्मवीर 'धीठ' ने अपनी हरियाणवी की लट्ठमार शैली में बगल वाले को कोहनी मारी और बोले, 'सुण भाई, यो राजा तो हम सब हैं, पर हमारा राज केवल राशन की लाइन में खड़ा होने तक सीमित है। ठाकुर साहब समानता का ऐसा पाठ पढ़ा रहे हैं जैसे भेड़िया बकरियों को शाकाहार का उपदेश दे रहा हो। यो जो सामने 'संविधान' की किताब रखी है, इसे देखकर तो ऐसा लागे है जैसे किसी अनपढ़ के हाथ में रॉकेट की मैनुअल बुक आ गई हो।' तभी मंच पर मुंशीराम ने घोषणा की कि अब 'गणतंत्र रत्न' पुरस्कार दिया जाएगा। सस्पेंस ऐसा बढ़ा जैसे किसी सस्पेंस फिल्म का क्लाइमेक्स हो। मुंशीराम ने चिल्लाकर नाम पुकारा– 'मंगल सिंह!' भीड़ में सन्नाटा छा गया। मंगल सिंह इस इलाके का वह सीधा-सादा किसान था जिसकी जमीन पिछले साल एक 'सड़क परियोजना' के नाम पर ठाकुर साहब के ही किसी करीबी ने हड़प ली थी। सबने सोचा कि शायद पश्चाताप का अमृत काल चल रहा है और ठाकुर साहब उसे सम्मान देकर अपनी छवि चमकाना चाहते हैं। मुंशीराम ने फिर पुकारा, 'मंगल सिंह, सामने आएं और अपना सम्मान स्वीकार करें!' पर कोई सामने नहीं आया। भीड़ में कानाफूसी होने लगी कि क्या मंगल सिंह ने इस 'पाखंड' का हिस्सा बनने से मना कर दिया है? या फिर प्रजातंत्र के इस नाटक में उसने अपनी चुप्पी को ही सबसे बड़ा विरोध मान लिया है?

सन्नाटा और गहरा गया, यहाँ तक कि झंडे के ऊपर मँडराते कौवे भी 'कांव-कांव' करना भूल गए। मुंशीराम के माथे पर पसीना ऐसे चमकने लगा जैसे सरकारी बजट में अचानक कोई बड़ा 'होल' दिख गया हो। ठाकुर साहब ने माइक थामा और भारी आवाज में बोले, 'मंगल सिंह शायद भावुक हो गए हैं, या फिर भीड़ में कहीं खो गए हैं। ये सम्मान उस त्याग का है जो एक साधारण नागरिक इस महान तंत्र के लिए करता है।' धर्मवीर 'धीठ' ने अपनी आँखों पर हाथ का छाजा बनाकर दूर तक देखा और फिर मूँछों पर ताव देते हुए बोले, 'त्याग भाई, त्याग तो मंगल सिंह ने तब कर दिया था जब उसकी बैलगाड़ी और दो बीघे जमीन ठाकुर के करिंदों ने 'विकास' की बलि चढ़ा दी थी। यो सम्मान नहीं, यो तो लाश पै मफलर डालने वाली बात है। मुंशी, तू जिस मंगल सिंह को पुकार रहा है, वो तो पिछले तीन महीने से तहसील के चक्कर काटते-काटते गायब हो गया है। या तो वो भगवान को प्यारा हो गया, या फिर इस 'समानता' के बोझ तले दबकर पाताल में समा गया। ठाकुर साहब का प्रजातंत्र तो वो है जहाँ हक मांगने वाले को 'गुमराह' और जान देने वाले को 'महान' घोषित कर दिया जावे है।' मंच पर मौजूद बड़े बाबू ने मुंशीराम के कान में कुछ कहा, जिसके बाद मुंशीराम का चेहरा पीला पड़ गया। घोषणा की गई कि मंगल सिंह की ओर से उनकी छोटी बेटी सम्मान लेने आएगी। एक दस साल की लड़की, जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी पर आँखों में वह सच था जो पूरी खाकी और खादी को झुलसा सकता था, मंच की ओर बढ़ने लगी।

वह लड़की मंच पर चढ़ी, तो ठाकुर साहब ने मुस्कराकर एक चमकदार शील्ड और एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। फोटोग्राफर ने चिल्लाकर कहा, 'सर, थोड़ा मुस्कुराइए, 'रिपब्लिक डे' का स्पेशल शॉट है!' ठाकुर साहब ने लड़की के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, पर उसने अपना सिर ऐसे झटक दिया जैसे कोई स्वाभिमानी देश अपनी बेड़ियाँ झटकता है। लड़की ने माइक के पास जाकर सिर्फ तीन शब्द कहे, जो पूरे 'घपला गंज' की फिजाओं में किसी बम की तरह फटे– 'मेरे बाबू कहाँ हैं?' मुंशीराम ने बात संभालते हुए कहा, 'बेटा, तुम्हारे बाबू तो देश की प्रगति के लिए 'अज्ञात' स्थान पर साधना कर रहे हैं, ये लो पैसे और घर जाओ।' लड़की ने वह लिफाफा खोला, तो उसमें से पैसे नहीं, बल्कि उसकी जमीन की नीलामी का वही पुराना नोटिस निकला जिस पर आज की तारीख में 'सफलतापूर्वक निस्तारण' की मुहर लगी थी। लड़की की आँखों से दो आंसू टपके और उसने वह शील्ड वहीं ठाकुर साहब के जूतों के पास पटक दी। सस्पेंस का पर्दा फाड़ते हुए धर्मवीर 'धीठ' चिल्लाया, 'देख लो भाई, यो है गणतंत्र! बाप को गायब कर दो और बेटी को शील्ड पकड़ा दो! मंगल सिंह तो उसी तहसील की नींव में दफन कर दिया गया जिसे आज तिरंगे से सजाया गया है। यो लड्डू नहीं, यो तो हमारी संवेदनाओं का कबाड़ा है।' वहाँ उपस्थित लोगों की आँखों में पानी तब आ गया जब उस लड़की ने तिरंगे की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोली, 'झंडा तो ऊंचा है साहब, पर इंसान बहुत नीचे गिर गया है।' ठाकुर साहब की गाड़ी सायरन बजाते हुए निकल गई, झंडा अब भी लहरा रहा था, पर उसकी परछाई में मंगल सिंह की बेटी अपना वह कागजी 'सम्मान' वहीं छोड़कर नंगे पैर भीड़ में खो गई। गणतंत्र दिवस खत्म हो गया था, और 'घपला गंज' फिर से उसी गड्ढे वाली सड़क पर अपनी 'स्वतंत्रता' के साथ रेंगने लगा था।

राजपथ से संघ ने दिया एकजुटता का संदेश

गणतंत्र दिवस

डॉ. लोकेन्द्र सिंह

लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं।

आज भी हम 1962 के भारत-चीन युद्ध को भूल नहीं पाते हैं। चीन ने भारत के विश्वास का कत्ल किया था। 'हिन्दी-चीनी, भाई-भाई' के हमारे नारे को धुंए में उड़ाकर चीन की कम्युनिस्ट सत्ता ने भारत पर अप्रत्याशित युद्ध थोप दिया था। हमारी सेना ने यथासंभव प्रतिकार किया। चीन को नाकों चने चबाने को मजबूर कर दिया। भारतीय सेना के शौर्य को देखकर चीन को अपने कदम रोकने पड़े। हालांकि, इस युद्ध में हमने बहुत कुछ खो दिया था। राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी चीन के साथ खड़ी थी, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण संदेश दिया। संघ के स्वयंसेवकों ने नागरिक अनुशासन, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सहयोग, घायल जवानों के प्राणों की रक्षा के लिए रक्त की आपूर्ति, युद्ध क्षेत्र में सैन्य रसद पहुँचाने में सहयोग एवं हवाई पट्टियों की सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों में आगे बढ़कर सहयोग किया। संकट के समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देशभक्ति को देखकर संघ के विरोधी रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का हृदय भी परिवर्तित हो गया। यही कारण रहा कि सरकार ने 26 जनवरी, 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए अन्य नागरिक संगठनों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके समविचारी संगठन भारतीय मजदूर संघ को राजपथ पर आमंत्रित किया। संघ के स्वयंसेवकों ने गणवेश पहनकर जब राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में हिस्सा लिया, तब स्वयंसेवक न केवल सबके बीच आकर्षण का केंद्र बने अपितु उन्होंने राष्ट्रीय एकजुटता के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन का संदेश भी दिया।

राजपथ (अब कर्तव्य पथ) 26 जनवरी, 1963 की राष्ट्रीय परेड कई कारणों से महत्वपूर्ण है। 1962 के चीनी आक्रमण के बाद देश का मनोबल डगमगाया हुआ था। ऐसे समय में राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन आवश्यक था। प्रश्न यह था कि जब भारतीय सेना सहित अन्य सुरक्षा बल भी सीमा रेखा पर हैं, तब राष्ट्रीय परेड किस प्रकार सम्पन्न की जाए। सुरक्षा कारणों से सेना को वापस भी नहीं बुलाया जा सकता था और राष्ट्रीय परेड की परंपरा को भी नहीं तोड़ सकते थे। तब विचार आया कि उन नागरिक संगठनों को परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाए, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में देश को संभालने में अपना योगदान दिया है। लोकसभा में 31 मार्च 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह तथ्य सबके सामने रखा कि ऐसी परिस्थिति में किसी ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुझाव दिया गया कि इस बार परेड में 'जनता का मार्च' होना चाहिए। दिल्ली नगर निगम के महापौर द्वारा स्थापित 'सर्वदलीय नागरिक परिषद' ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसे संघ के स्थानीय अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया। सरकार के आमंत्रण पर, केवल दो दिन की तैयारी में संघ के लगभग 3000 गणवेशधारी स्वयंसेवक राजपथ पर कदम से कदम मिलाकर संचलन कर रहे थे, जिसमें लगभग 100 स्वयंसेवकों का घोष दल भी शामिल था। स्वयंसेवकों की यह टुकड़ी जिस प्रकार अनुशासनबद्ध होकर राजपथ पर संचलन कर रही थी, भारतीय सेना की अनुशासित टुकड़ी की भाँति ही नजर आ रही थी। अगले दिन समाचार पत्रों में स्वयंसेवकों की तस्वीरें भी प्रकाशित हुईं और संवाददाताओं ने यह भी संकेत दिया कि जनता के बीच सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र स्वयंसेवकों का अनुशासित दल ही था। दैनिक समाचारपत्र 'हिन्दुस्तान' ने परेड की जो तस्वीरें प्रकाशित की, उसमें स्वयंसेवकों के संचलन की तस्वीर भी शामिल थी। हिन्दुस्तान में प्रकाशित समाचार में लिखा गया कि 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों का प्रदर्शन बहुत आकर्षक रहा'। इसी प्रकार, द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक समाचार में उल्लेख किया गया है कि संघ के अनुषांगिक संगठन 'भारतीय मजदूर संघ' ने भी परेड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।कुछ वर्षों तक कम्युनिस्ट एवं कांग्रेस समर्थित लेखकों/पत्रकारों ने 1963 के गणतंत्र दिवस की परेड में संघ के शामिल होने को सिरे से खारिज किया। लेकिन, जब उस समय के समाचारपत्रों में प्रकाशित चित्र, समाचार और सिलेक्टिव वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में प्रकाशित सामग्री सामने आई, तब नये प्रकार के कुतर्क गढ़े जा रहे हैं। इस सबके बीच निर्विवाद सच यही है कि संकट के समय में संघ ने अपने कर्तव्यों का पालन किया और राष्ट्रीय परेड में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। संघ विरोधी खेमे में यह खलबली उस समय भी थी, जब यह जानकारी सामने आई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय परेड में शामिल हो रहा है। दैनिक समाचारपत्र 'हिन्दुस्तान' ने 25 जनवरी, 1963 को 'रा. स्व. संघ भी परेड में भाग लेगा' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया। कई लोगों ने संघ के स्वयंसेवकों को रोकने के लिए भरसक प्रयास किए लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे लोगों को फटकार कर भगा दिया और साफ कहा कि वे संघ को परेड में शामिल होने से नहीं रोक सकते हैं। 27 जनवरी को कांग्रेस की एक बैठक में इस विषय में काफी चर्चा हुई। इसका विवरण सिलेक्टिव वर्क ऑफ जवाहरलाल नेहरू में प्रकाशित है। बैठक में पंडित नेहरू ने बताया था कि 'कुछ कांग्रेसियों ने उनसे शिकायत की थी कि संघ वाले गाजियाबाद और मेरठ से वर्दीधारी लोग (स्वयंसेवक) जमा कर रहे हैं'। कांग्रेस के नेताओं ने पंडित के सामने यह दुख भी जाहिर किया कि हमारे पास इतनी वर्दी नहीं है। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता भी परेड में दिखाई नहीं दिए। तब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उन लोगों को स्पष्ट कहा कि 'मैं तो नहीं रोक सकता आरएसएस को आने से, (किसी को भी आने से रोकना) बहुत गलत बात है'। इसका अर्थ है कि सब प्रकार से जानकारी होने और कांग्रेसियों का विरोध होने के बाद भी नेहरू जी ने संघ को राष्ट्रीय परेड में शामिल होने दिया।

याद रखें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1962 के युद्ध के समय ही नहीं बल्कि उसके बाद हुए युद्धों में भी भारत सरकार के साथ खड़े रहकर अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन किया है। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भी संघ ने दिल्ली की यातायात व्यवस्था, रणनीतिक ठिकानों की पहरेदारी, सैनिकों के लिए भोजन एवं रसद की आपूर्ति, नागरिक सुरक्षा एवं अनुशासन का पालन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारीलाल नंदा ने स्वयंसेवकों के कार्य की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की और आकाशवाणी पर उनके योगदान का जिक्र किया। याद हो कि युद्ध प्रारंभ होते ही राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर 'श्रीगुरुजी' के साथ ऐतिहासिक चर्चा भी की थी। 1971 के युद्ध के दौरान सैनिकों के लिए 24 घंटे भोजन एवं दवा की आपूर्ति, अपनी जान बचाकर भारत आए हिन्दू एवं मुस्लिम शरणार्थियों के लिए राहत शिविर, युद्ध में घायलों के लिए रक्तदान महायज्ञ और हवाई पट्टियों की मरम्मत जैसे कार्य स्वयंसेवकों ने किए। उनकी देशभक्ति एवं निस्वार्थ सेवाभाव को देखकर सेना प्रमुख जनरल (बाद में फील्ड मार्शल) सैम मानेकशॉ ने कहा था कि 'इन युवाओं की निस्वार्थ सेवा, फुर्ती और अनुशासन देखकर मुझे गर्व होता है। अगर सेना के बाद देश में कोई सबसे अनुशासित संगठन है, तो वह यही है'। कहना होगा कि प्राकृतिक, मानवीय आपदा से लेकर किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय संकट के समय में संघ सिद्ध करता है कि वह सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचार का संगठन है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष के प्रसंग पर भारत सरकार ने जिस स्मृति डाक टिकट को जारी किया है, उसमें भी 1963 की गणतंत्र दिवस में शामिल स्वयंसेवकों के समूह का चित्र शामिल किया गया है। इसके साथ ही एक दूसरे चित्र में सेवा एवं राहत कार्य करते स्वयंसेवक दिखायी दे रहे हैं। संघ शताब्दी वर्ष के प्रसंग पर सरकार ने एक बार फिर 'राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष' की संघ यात्रा का स्मरण देशवासियों को कराया।

भारत में गणतंत्र की चुनौतियाँ, विफलताएँ और समाधान

गणतंत्र दिवस

अरुण कुमार डनायक

(लेखक गांधी विचारों के अध्येता व समाजसेवी हैं)

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर भारत ने स्वयं को संप्रभुता संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। यह केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का उत्सव नहीं था, बल्कि यह नैतिक और राजनीतिक संकल्प भी था कि सत्ता वंशगत स्वामित्व में नहीं होगी, बल्कि संविधान के अधीन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होगी।

लेकिन आज भारत में लोकतंत्र गहरे संकट से गुजर रहा है। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा को साकार करने वाला संतुलित तंत्र है, जिसमें विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज की भूमिका होती है। विगत कुछ वर्षों में यह संतुलन कई मोर्चों पर धँसता दिख रहा है, जिससे गणतंत्र की मूल भावना कमजोर पड़ी है। आज लोकतांत्रिक व संवैधानिक संस्थाओं की कार्यवाही में गिरावट स्पष्ट रूप से दिख रही है। संसद की बैठक के दिन घट रहे हैं और महत्वपूर्ण विधेयक बहस के बजाय शोर-शराबे के बीच पारित किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का उदाहरण उल्लेखनीय है, जिन्होंने यह सिद्धांत स्थापित किया कि सदन की कार्यवाही यदि नियमों के अनुरूप न हो तो किसी भी विधेयक को पारित कराना संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है, और इसी कारण उन्होंने अव्यवस्थित सदन में विधेयक पारित कराने से इंकार किया।

संसद के पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि वे निष्पक्षता बनाए रखें और इसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित भी करें। अक्सर उनके द्वारा सत्ता पक्ष को संरक्षण देते हुए विपक्ष की स्थगन प्रस्ताव या चर्चा संबंधी मांगें खारिज कर दी जाती हैं। इससे न केवल निर्णय-प्रक्रिया अपूर्ण होती है, बल्कि संसद का विमर्शात्मक चरित्र भी कमजोर होता है। मंत्रियों द्वारा सदन को गुमराह किये जाने पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके बावजूद मंत्री अक्सर गलत जानकारी सदन पटल पर रखते हैं। आज संसद संवाद के मंच के बजाय एक औपचारिक संस्था बनती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास गहराता जा रहा है। गणतंत्र की विफलताओं में एक बड़ा कारण पर्यावरण और विकास नीतियों पर संसद में गंभीर और प्रभावी विमर्श की कमी है। पिछले दशक में 'तेज़ विकास' की प्राथमिकता ने हिमालयी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में पर्यावरणीय संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उत्तराखंड की चार धाम सड़क परियोजना और कश्मीर में सुरंग निर्माण ने पहाड़ों की अनियंत्रित कटाई और विस्फोटक प्रयोग से ढलानों की स्थिरता नष्ट की, जिससे भूस्खलन और ज़मीन धँसने की घटनाएँ बढ़ीं। सात बहनों के पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण ने वनों, पहाड़ी ढलानों और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित किया, जिससे स्थानीय आबादी और यातायात की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। यह स्पष्ट करता है कि विकास योजनाएँ दूरदर्शिता के बजाय केवल सड़क निर्माण तक सीमित रह गईं। विकास की अदूरदर्शिता का स्पष्ट उदाहरण हवाई संपर्क विस्तार है। 'उड़ान' योजना के तहत 2016 के बाद सैकड़ों मार्ग और 70 से अधिक हवाई अड्डे चालू किए गए, लेकिन कई व्यावसायिक रूप से टिकाऊ नहीं हो पाए। दिसंबर 2025 तक जोड़े गए लगभग दो दर्जन हवाई अड्डे, जैसे पठानकोट, शिमला, लुधियाना और राउरकेला, अस्थायी या पूर्णतः बंद रहे। उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में खोले गए कई हवाई अड्डों पर भी नियमित उड़ानें नहीं चल सकीं, और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दर्जनों हवाई अड्डों ने भारी घाटा उठाया। यह दर्शाता है कि केवल हवाई अड्डे बनाना विकास नहीं, बल्कि दिखावटी उपलब्धि बनकर रह जाता है।

यदि इन विकास परियोजनाओं पर पहले संसद में गंभीर बहस होती और जनता व विशेषज्ञों से व्यापक विमर्श किया जाता, तो पर्यावरणीय खतरे और दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता था। उच्चतम न्यायालय का समय पर हस्तक्षेप, जैसा कि हाल ही में अरावली पर्वत मामले में हुआ, ढलानों और नदियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। भारत में संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी ने गणतंत्र को कमजोर किया और हमें असुरक्षित तथा अधूरे विकास के मार्ग पर डाल दिया।

कौशल विकास केंद्र, नर्सिंग, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी महाविद्यालयों में विस्तार के बावजूद गुणवत्ता नियंत्रण की उपेक्षा स्पष्ट है। सीटों की संख्या बढ़ी है, लेकिन प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी के कारण जनता गुणवत्तापूर्ण सेवाओं और सामाजिक विकास के लाभ से वंचित रही है। जाति, धर्म, भाषा और वर्ग के आधार पर सामाजिक विभाजन लोकतंत्र की एकता के लिए खतरा हैं। आर्थिक असमानता, बेरोज़गारी और बुनियादी मानव सुविधाओं जैसे शुद्ध पेय जल, पक्के आवास और सस्ता सार्वजनिक परिवहन में असमान अवसर लोकतंत्र को जन-विश्वास की कमी की ओर ले जा रहे हैं। गणतंत्र तभी सफल कहा जा सकता है जब सभी नागरिक – ग्रामीण, दलित, महिला, पिछड़ा वर्ग या आदिवासी – शासन के निर्णयों और नीतियों में संतुलित रूप से शामिल हों। आज सांसदों और विधायकों को प्रभावित करने के लिए नए-नए राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग, सतर्कता आयोग, सूचना आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता कमजोर हुई है, जबकि ईडी और सीबीआई का उपयोग विपक्ष पर दबाव बनाने के औज़ार के रूप में बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं की निष्पक्ष जाँच, भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण और सूचना के पारदर्शी प्रवाह पर प्रतिकूल असर पड़ा है, जिससे राष्ट्रीय संसाधनों के वित्तीय दुरुपयोग से जुड़े मामलों में वृद्धि हुई और संसद का प्रभावी नियंत्रण क्षीण हो गया। यह हमारे गणतंत्र की एक गंभीर विफलता है।

लोकतंत्र की असली कसौटी यह है कि सत्ता का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे। यदि यह केवल शहरों सीमित रह जाए, तो गणतंत्र की मूल भावना अधूरी रह जाती है। इसलिए नीति-निर्माण में स्थानीय समुदायों, ग्राम पंचायतों की सहभागिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना उतना ही आवश्यक है जितना राज्यों और केंद्र के बीच संतुलन बनाए रखना।

भारत का गणतंत्र अभी अधूरी यात्रा पर है और तभी पूर्ण होगा जब नागरिकों की सशक्त, सुशिक्षित और प्रभावी सहभागिता लोकतंत्र की असली नींव के रूप में सुनिश्चित हो। महात्मा गांधी के आदर्शों की अनदेखी के कारण हमारा गणतंत्र वांछित लक्ष्यों तक नहीं पहुँच पाया। आज उनकी सलाह-लोक सेवकों द्वारा सरल जीवन-शैली अपनाना, सार्वजनिक धन का विवेकपूर्ण उपयोग करना और पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास में जनता की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना–को लागू कर लोकतंत्र की नींव को सशक्त बनाया जा सकता है। गणतंत्र की सच्ची जीत तब होगी जब सत्ता का लाभ हर नागरिक तक पहुँचे, नीति-निर्माण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पारदर्शिता और जवाबदेही हो, और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

वसंत तुम आना

श्रीति राशिनकर

वसंत तुम आना और रुक जाना
सदा के लिए मेरे आंगन में
ताकि देख सकूं तुम्हे दिन रात
वसंत तुम आना और रुकना मेरे सपनों में
निहार सकूं नींद में भी तुम्हे वसंत तुम आना और
रुकना मेरी हंसी में ताकि मैं सदा खिलखिला सकूं तुम्हारे साथ
वसंत तुम आना और रुकना फूलों की गंध में
ताकि मैं अपनी सांसों में बसा लूं तुम्हे
वसंत तुम आकर बस जाना सप्त स्वरों में
ताकि झंकृत हो सके वीणा का हर तार!
वसंत तुम आ जाना बिना दस्तक दिए मेरे घर में
ताकि मैं पूरी जिंदगी बिता सकूं खुशी के साथ
वसंत तुम आना और रुक ही जाना
पल – पल हर अहसास में ताकि बाट सकूं खुशी सबके साथ
वसंत तुम आना बच्चा बन मेरे पास
ताकि मैं खुद ही बच्चा बन जाऊं ताउम्र!

प्रवासी भारतीय- मातृभूमि से विश्व तक सांस्कृतिक सेतु

गणतंत्र दिवस

अशोक श्रीवास्तव

कनाडा निवासी लेखक भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् दिल्ली के सेवानिवृत अधिकारी हैं।

प्रवासी भारतीय केवल भौगोलिक दूरी पर बसे नागरिक नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति के जीवंत संवाहक हैं। विश्व के विभिन्न देशों में रहते हुए भी उन्होंने अपनी भाषा, परंपरा, पर्व, संस्कार और जीवन-दर्शन को जीवित रखा है। 'भारतीय संस्कृति हमारे डीएनए में है।' 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का यह बयान भारत के वैश्विक प्रभाव और प्रवासी भारतीयों की भूमिका का प्रतीक है।

गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का आगमन केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि सभ्यतागत संवाद का प्रतीक था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इंडोनेशियाई समाज में भारतीय प्रभाव गहराई से विद्यमान है और कई नाम संस्कृत मूल से प्रेरित हैं।

गणतंत्र दिवस पर यह स्मरण करना आवश्यक है कि, भारतीय प्रतिभा सीमाओं से परे जाकर विश्व-पटल पर भारत का गौरव बढ़ा रही है। ब्रिटिश-भारतीय इंजीनियर लीना गाडे इसका सशक्त उदाहरण हैं, जिनका उल्लेख कौन बनेगा करोड़पति के 7 करोड़ रुपये के प्रश्न में भी हुआ–यह दर्शाता है कि प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियाँ अब राष्ट्रीय गर्व और सामूहिक प्रेरणा का हिस्सा बन चुकी हैं। लीना गाडे ने प्रतिष्ठित 24 Hours of Le Mans रेस में इतिहास रचते हुए पहली महिला रेस इंजीनियर बनने का गौरव प्राप्त किया। इसी तरह तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में सत्य नडेला और सुंदर पिचाई, राजनीति और शासन में ऋषि सुनक (ब्रिटेन के प्रधानमंत्री), लियो वराडकर (आयरलैंड के प्रधानमंत्री) और प्रविंद जुगनौत (मॉरीशस के प्रधानमंत्री) भारतीय मूल की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को रेखांकित करते हैं। विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में डॉ. सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर (भौतिकी में नोबेल पुरस्कार) और वेंकट्रामन रामकृष्णन (रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार) जैसी विभूतियों ने भारत की बौद्धिक परंपरा को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाई है। इसी प्रकार कला, साहित्य, मीडिया तथा खेल के क्षेत्रों में भी अनेक भारतीय मूल के व्यक्तित्व विश्व-मंच पर भारत का नाम ऊँचा कर रहे है।

व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में भी प्रवासी भारतीयों का योगदान कम नहीं है। इंडियन-बाल्टिक चैंबर, Indo-UAE और Indo-Russia-Indo France जैसे मंच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। भारतीय व्यवसायी विदेशी अर्थव्यवस्था में योगदान देने के साथ भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ा रहे हैं। प्रवासी भारतीयों की रेमिटेंस भारतीय अर्थव्यवस्था का मज़बूत आधार हैं, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव इससे भी बड़ा योगदान देता है।

आज प्रवासी भारतीय केवल 'भारत-विश्व सेतु' नहीं हैं; वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की सशक्त, सकारात्मक और सम्मानजनक छवि बनाने में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। वे न केवल भारत को दुनिया से जोड़ते हैं, बल्कि अपनी मेहनत, प्रतिभा और मूल्यों के बल पर भारत का गौरव बढ़ाते हैं। G-20 की अध्यक्षता के दौरान 'वसुधैव कुटुम्बकम्' कोई नारा नहीं, बल्कि व्यावहारिक वैश्विक दृष्टि बनकर सामने आया।

भारत 2026 में ब्रिक्स का अध्यक्ष देश है इसके तहत विश्व में शांति सहयोग और संतुलन का पथ प्रदर्शक बन रहा है।

वैश्विक मंच पर भारत की सैन्य और रणनीतिक उपस्थिति भी लगातार सशक्त हो रही है। वर्ष 2023 में फ्रांस के Bastille Day Parade में भारतीय सेना और वायुसेना की भागीदारी विशेष महत्व रखती है। फ्रांस सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सैन्य नेतृत्व को दिया गया विशेष आमंत्रण भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की मजबूती का प्रतीक था। भारतीय सैनिकों का अनुशासन और वायुसेना की भव्य झाँकी ने यह स्पष्ट किया कि भारत आज न केवल क्षेत्रीय, बल्कि वैश्विक शक्ति के रूप में भी पहचाना जा रहा है।

प्रवासी भारतीय विदेशी समाज में पूरी तरह घुलने-मिलने के बावजूद अपनी सांस्कृतिक पहचान नहीं खोते। भाषा और उच्चारण बदल सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं बदलते। बच्चों के नाम, पर्व-त्योहार, पूजा-पाठ, विवाह और पारिवारिक परंपराओं में भारत जीवित रहता है। त्रिनिदाद-टोबैगो जैसे देशों में लोग आज भी 'सीता-राम' कहकर अभिवादन करते हैं और धार्मिक अवसरों पर पारंपरिक आचारों का पालन करते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई और बाल्टिक देशों में भी जीवित है।

भारत की विदेश नीति में प्रवासी भारतियों की सुरक्षा के लिए स्थायी प्रावधान है । हाल के वर्षों में ईरान, यूक्रेन, सूडान और यमन जैसे संकटग्रस्त क्षेत्रों से भारतीयों की सुरक्षित वापसी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत सरकार का प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिक दायित्व है। 'ऑपरेशन सिंधु', 'ऑपरेशन गंगा', 'वंदे भारत मिशन' और 'ऑपरेशन कावेरी' जैसे अभियानों ने यह संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों और प्रवासी समुदाय को दुनिया के किसी भी कोने में अकेला नहीं छोड़ता।

विदेशों में आयोजित भारतीय संस्कृति के प्रतीक कार्यक्रम न केवल प्रवासी भारतीयों को मातृभूमि से जोड़ते हैं, बल्कि विश्व समुदाय के सामने भारत की सभ्यतागत पहचान को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करते हैं।

21 जून को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ,भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य , कर्नाटक संगीत आदि को प्रदर्शित करने वाला 'फेस्टिवल ऑफ इंडिया' का आयोजन अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका में किया जाता है। जो अगली पीढ़ी को भाषा और परंपराओं से जोड़ते हैं और भारत की सकारात्मक छवि का निर्माण करते है।

सांस्कृतिक आत्मविश्वास का एक और प्रतीक 20 जनवरी 2025 को अमेरिका में देखने को मिला, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ-ग्रहण अवसर पर आयोजित 60वीं सैन्य परेड में भारतीय ढोल-ताशा की गूंज सुनाई दी। यह केवल सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि यह संकेत था कि भारतीय संस्कृति अब विदेशी रंग में नहीं, बल्कि अमेरिकी सार्वजनिक जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन चुकी है।

गणतंत्र दिवस 2026 पर यूरोपीय संघ के नेताओं उर्सुला वॉन डेर लेयेन (यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष) तथा एंटोनियो कोस्टा (यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष) की भागीदारी इस बात का संकेत है कि भारत अब बहुपक्षीय वैश्विक नेतृत्व की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इस परिवर्तन को प्रवासी भारतीय समुदाय गर्व, अपनत्व और आत्मविश्वास के साथ अनुभव कर रहा है। गणतंत्र दिवस आज केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि यह भारत के वैश्विक उदय, सांस्कृतिक आत्मसम्मान और प्रवासी भारतीयों के योगदान का उत्सव बन चुका है।

गौण होते गण का पर्व

गणतंत्र दिवस

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। एक महान पर्व। इसे हमें सगर्व और सोल्लास मनाना चाहिये। यह औपनिवेशिक-दासता से मुक्ति के करीब ढाई साल के बाद उस ऐतिहासिक प्रसंग से जुड़ा है, जब हमारे नव-स्वतंत्र महादेश ने सार्वभौमिकता अख्तियार की। इस दिन हमारा अपना संविधान लागू हुआ। राजवंश समाप्त हुये। राजे-महाराजे भूतपूर्व की तालिका में वर्गीकृत हुये। गणतंत्र का उदय हुआ। हमारा अपना संविधान लागू हुआ; एक ऐसा संविधान जो गहन-विमर्श और विचार-मंथन के उपरांत अस्तित्व में आया था। संविधान सदाशयी, समदर्शी और सामासिक था। उसमें कोई खोट न था। उसके लिए सब समान थे। ऊंच-नीच, जाति-धर्म, गरीब-अमीर, अस्पृश्य-सवर्ण, सबल-निर्बल, स्त्री-पुरुष, गारे-काले में कोई भेद नहीं। यह जनगण का संविधान था। इसमें, किसी व्यक्ति, समुदाय या युति की नहीं, 'वी द पीपुल' की निर्विवाद और घोषित महत्ता थी। यह हम भारत के लोगों की एक महान लोकतांत्रिक राष्ट्र रचने के स्वप्न और संकल्प की अभिव्यक्ति थी। उसकी पृष्ठभूमि में तरल और सान्द्र अनुभूतियों का सागर लहराता था। वह सबको समान अधिकार, सबको समान अवसर और सबके उत्थान का घोषणा पत्र था। यकीनन यह इतिहास में पहली बार हो रहा था। इस नाते वह क्षण गौरवशाली था, जब हमारा संविधान लागू हुआ। छब्बीस जनवरी का दिनांक इतिहास के फलक पर सुनहरी इबारतों में अंकित हुआ। हमारी संविधान निर्मात्री सभा में तपःपूत जनों का बाहुल्य था। अधिकांश का व्यक्तित्व स्वतंत्रता-संग्राम की आग में तपे कुन्दन सरीखा था। महात्मा के प्रभामंडल का आलोक ओरछोर व्याप्त था। लक्ष्य स्पष्ट था। संविधान ने बरबस कोटि-कोटि भारतीयों के लिये निर्दिष्ट की ओर बढ़ने की न सिर्फ पीठिका रची, बल्कि उन्हें प्रेरणा, परिवेश, अवसर और संबल भी प्रदान किया। हम आगे बढ़े। अघातों और अवरोधों के बावजूद। स्वप्नदृष्टा प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा, 'आराम हराम है।' नये औद्योगिक तीर्थ स्थापित हुये। हरित और श्वेत क्रांति हुई। भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। परमाणु विस्फोट से वह महाशक्तियों के क्लब में शरीक हुआ। निर्गुट आंदोलन ने उसे वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दी। बीसवीं सदी का समूचा उत्तरार्द्ध भारत के चतुर्मुखी विकास और उत्थान का अदभुत कालखंड था। और यह संभव हो सका था हमारे अनूठे संविधान की बदौलत। अर्द्धशती के इस अंतराल में भारतीय प्रतिभाओं ने सारे विश्व को चमत्कृत किया। यकीनन इससे भारत का मान बढ़ा और विश्व के तमाम राष्ट्रों में भारत के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव निर्मित हुआ। भारत में विभिन्न धर्मों और जातियों के सह-अस्तित्व ने वैश्विक स्तर पर भारत की अनूठी और आकर्षक छवि निर्मित की। बीती दहाइयों में हमने हमने शीर्ष पदों पर महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों को बैठे देखा। इनमें लौह महिला श्रीमती इंदिरा गाँधी ने नया इतिहास रचा और डॉ. एपीजे कलाम जीते-जी भारत रत्न से सम्मानित हुये। किस्सा कोताह यह कि हमारा संविधान हमारी ताकत बना और उसने इस महादेश के मेरुदण्ड को सीधा और सुदृढ़ रखने के साथ-साथ धमनियों और शिराओं में रक्त के प्रवाह को कायम रखा। ऐसा नहीं है कि तीन चौथाई सदी में विकृतियां नहीं पनपीं। देश की परखनली में जब-तब अंतःक्रियाओं से मटमैला अवक्षेप भी उपजा, लेकिन वह कभी भी देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता के लिये खतरा नहीं बन सका। यकीनन सत्ताधीशों से गलतियाँ तो हुईं, लेकिन उनकी सदाशयता कभी संदेह के घेरे में नहीं आई। हाँ, हमने एक बड़ी गलती जरूर की कि हमने नागरिकता-बोध और सेक्यूलर मनस विकसित नहीं किया। हमने विभेदकारी, तंग जेहन और मजहबी तत्वों की जड़ों में मट्ठा नहीं डाला। फलतः उसमें कल्ले फूटते गये और उनका तेजी से पनपना जारी रहा।

कुछ देर को हम समय के गलियारे में उलटे पांव चलें। संविधान-सभा की बहसों और कार्यवाही को याद करें। संविधान-निर्माताओं के मन में आशंकायें कम नहीं थीं। डॉ. अंबेडकर और उनके सहयोगी भविष्य के खतरों को बूझ रहे थे। सभा के सदस्यों ने जब-तब अपनी चिंताओं का इजहार भी किया था। स्वयं डॉ. अंबेडकर को डर था कि कहीं अच्छा संविधान बुरे हाथों में न चला जाये। पंथनिरपेक्षता को अपनाने के पीछे गहन चिंतन और इतिहास के गूढ़ सबक का हाथ था। संविधान ने सभी पंथों व धर्मों को सम्मान व स्वतंत्रता दी और किसी एक को न तो वरीयता दी और न ही किसी को राजकीय धर्म घोषित किया। यह वक्त का तकाजा था और भविष्य में सर्वांगीण विकास की आधारशिला भी। यह इस महादेश में फासीवाद को रोकने की पेशकदमी भी थी। गौरतलब है कि आजादी से पहले ही 24 जनवरी, सन् 47 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की सदारत में अल्पसंख्यकों समेत नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान तय करने के लिये सलाहकार समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में जोर देकर कहा था कि देश में समता का अधिकार होना चाहिये, छुआछूत शोषण और भेदभाव की समाप्ति होनी चाहये। एतदर्थ सरकार की ओर से किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। रपट में कहा गया था कि छुआछूत को हर हाल में खत्म किया जायेगा और इसमें किसी भी असमर्थता को बरतना अपराध समझा जायेगा। आज के परिदृश्य को देखें तो चिंता का तब का औचित्य समझ में आता है। संविधान सभा की सारगर्भित कार्यवाही को देखें। सदस्य-द्वय प्रमथ रंजन ठाकुर और सैयद अब्दुल रऊफ ने जो कहा था, वह वक्त की कसौटी पर सही उतर रहा है। सदाशयता, सौजन्य और शालीनता का दायरा सिमटा है और दुराशयता, हिंसा और घृणा का विस्तार बेरोकटोक जारी है। जेमिमा रोड्रिग्स और डॉ. इनार्मुरहमान के प्रकरण क्या दर्शाते हैं? आज हम घृणा और विद्वेष के विषाक्त वातावरण में जी रहे हैं। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। आदमी न हुआ, कबर बिज्जू हो गया। वृहत्तर समाज के धार्मिक-सांस्कृतिक उत्सव राजकीय पर्व हो गये हैं। दशा हम देख रहे हैं और दिशा भयावह है। बोगदे का सिरा अराजकता के कुहासे में खुलता है। चिंतनीय यह भी है कि आज गणतंत्र में गण लगातार गौण होता जा रहा है और तंत्र शक्तिशाली। और तो और गण के अनुकूल होने के विपरीत तंत्र स्वेच्छाचारिता की ओर बढ़ रहा है। अतीत में खतरनाक और जहरीली प्रवृत्तियों को 'इग्नोर' या अनदेखा करना भारी पड़ा है। ऐसे में गांधी फिर-फिर याद आते हैं। उनका 'ताबीज' अभी खोया नहीं है। गांधी के सबक और संविधान हमें बचा सकते हैं। अलबत्ता यह आसाँ नहीं, दुश्वार है, मगर हमें संविधान को बचाना होगा। उसमें इस महादेश की आत्मा प्रतिबिंबित है। गणतंत्र दिवस इसी समवेत संकल्प का दिवस है। सदियों बाद अनगिन त्याग और बलिदान से उदित हमारा गणतंत्र अक्षुण्ण रहे, यही हमारा दायित्व है।

बैतूल के लाड़ले मोहन नागर को मिला पद्मश्री का राष्ट्रीय सम्मान

बैतूल के भारत भारती शिक्षा संस्थान के सचिव मोहन नगर को पद्श्री पुरस्कार मिलने की घोषणा से खुशी की लहर

तीन दशक से पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में किए उल्लेखनीय कार्य

एस.के. द्विवेदी, बैतूल। भारत भारती शिक्षा संस्थान से सचिव, राजगढ़ के लाड़ले और तीन दशकों से समाज सेवा, शिक्षा और जल संरक्षण समेत पर्यावरण संवारने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले मोहन नगर को वर्ष 2026 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित करने की हाल में घोषणा हुई है। इससे बैतूल जिले समेत भारत भारती संस्थान के पदाधिकारियों में खुशी की लहर है। संभवतः श्री नागर बैतूल से जुड़े पहले ऐसे शख्स है, जिनका चयन उपरोक्त कार्यों को देखते हुए पद्मश्री पुरस्कार के लिए किया गया है। भारत भारती शिक्षण संस्थान से जुड़कर, उन्होंने न केवल वनवासी शिक्षा समेत अन्य प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया, इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी उन्होंने लोगों को जोड़कर 75 से अधिक पहाड़ियों को हरा भरा करने का भी काम किया इसके अलावा गंगावतरण अभियान चलाकर जल संरक्षण के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उनके इन संघर्ष को देखते हुए ही भारत सरकार ने पदम श्री सम्मान से उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की है।

जीवन परिचय पर एक नजर

नाम- मोहन नागर
पिता- स्व.श्री भंवरलाल लाल नागर
माता- स्व. श्रीमती गुलाबदेवी नागर
जन्मतिथि- 23-02-1968
शिक्षा- एम. ए. राजनीति विज्ञान, (विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन)
पद... उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन)
-सचिव भारत भारती शिक्षा संस्थान, बैतूल

इन सम्मान से हो चुके सम्मानित.. भारत भारती शिक्षण संस्थान के सचिव मोहन नागर के पहले भी कई सामानों से सम्मानित हो चुके हैं, इनमें प्रमुख रूप से नदी व जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने हेतु वर्ष 2019 राष्ट्रीय 'जल प्रहरी' सम्मान से दिल्ली में सम्मानित किया गया। जल संरक्षण के ही क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2020 में 'वाटर हीरो' सम्मान से सम्मानित किया गया।

मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा गौ सेवा के लिए 'गोपाल पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मध्यप्रदेश शासन की साहित्य अकादमी द्वारा स्वयं की काव्य कृति 'चातुर्मास' को दुष्यंत कुमार साहित्य अकादमी पुरस्कार से महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। भूगर्भ जल संरक्षण के लिए भाऊराव देवरस राष्ट्रीय पुरस्कार से दिल्ली में सम्मानित किया जा चुका है।

इन पदों को किया सुशोभित..

समाजसेवी श्री नागर भारत भारती शिक्षण संस्थान के सचिव पद के अलावा वर्तमान में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी जबलपुर प्रबंधन मण्डल के सदस्य, मध्यप्रदेश शासन वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष है।

ये रहा सबसे खास काम..

जिले भर की 75 पहाड़ियों में पौधे लगाकर किया हराभरा....

सोनाघाटी की, जो पहाड़ी कुछ साल पहले तक बंजर और वीरान नजर आती थी, उसे हरा-भरा करने के लिए पंद्रह लोगों ने गंगा अवतरण अभियान की शुरुआत की थी, जिससे प्रेरणा लेकर बाद में हजारों पर्यावरण प्रेमी इस अभियान से जुड़ते चले गए। इन पर्यावरण प्रेमियों ने न सिर्फ सोनाघाटी पहाड़ी, बल्कि जिले भर की लगभग 75 पहाडियों को भी हरा-भरा करने के लिए पौधे लगाए। इसी का फल है कि आज जिले की अधिकांश पहाड़ियां हरियाली से लहलहा रही है।

वर्षा जल को भूमि में उतारने खोदी खंती...

सोनाघाटी पहाड़ी की 60 एकड़ भूमि को इसके लिए चिन्हित किया गया और मई 2017 से पहाड़ी का पूजन कर गंगावतरण अभियान की शुरुआत की गई। जिसमें पहले चरण में 1800 खंतीयां खोदकर उसमें करीब दो हजार पौधे लगाए गए। बाद में इस 60 एकड़ पहाड़ी जमीन पर लगभग 8000 खंतियां खोदी गई और 32000 पौधे लगाए गए। खंती खोदने के बाद बारिश के दौरान इसमें पौधे लगाए गए।

16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जिला स्तरीय आयोजन

एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

बैतूल। 16 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी को जिला स्तरीय आयोजन संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन परिसर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन, अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अनिता पटेल, एसडीएम डॉ.अभिजीत सिंह, तहसीलदार बैतूल पुनम साहू, नायाब तहसीलदार श्याम उइके उपस्थित थे। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का

शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों, बीएलओ, सुपरवाइजर, शिक्षक, ऑपरेटर एवं फील्ड स्टाफ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, वहीं नवीन मतदाताओं को एपिक कार्ड वितरित किए गए। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अक्षत जैन ने कहा कि मतदाता दिवस का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को उसके मौलिक अधिकार के प्रति जागरूक करना है, ताकि कोई भी नागरिक मतदान से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटि रहित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुनियोजित ढंग से कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर के नेतृत्व में बैतूल जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में ईआरओ, एईआरओ, सुपरवाइजरो, बीएलओ की नियुक्ति की गई और निर्वाचन आयोग की संरचना के अनुरूप कार्य किया गया। इस विशेष गहन पुनरीक्षण में बैतूल जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, जिसके लिए आज भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य केवल एक विभाग का नहीं, बल्कि समस्त शासकीय अमले का सामूहिक प्रयास होता है। विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक, ऑपरेटर एवं फील्ड स्टाफ ने मिलकर इस कार्य को सफल बनाया।

लोकतंत्र की धडक़न हैं मतदाता: एसडीएम- बैतूल एसडीएम ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो संविधान के अनुसार संचालित होता है। लोकतंत्र की मजबूती मतदाताओं की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है, इसी उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी, जबकि वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। उसी परंपरा के अंतर्गत वर्ष 2026 में 25 जनवरी को देशभर में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम मेरा भारत, मेरा वोट निर्धारित की गई है।

जिले में 11 लाख 95 हजार 558 मतदाता पंजीकृत- एसडीएम ने बताया कि बैतूल जिले में कुल 11 लाख 95 हजार 558 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 6 लगभग 95 हजार 15, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 5 लाख 86 हजार 27 है। वहीं 16 अन्य कैटिगरी के मतदाता शामिल है।

उत्कृष्ट विद्यालय में हुई एनसीसी ए सर्टिफिकेट की परीक्षा

जूनियर डिवीजन के 139 कैडेटस हुए शामिल

बैतूल। एनसीसी के ए सर्टिफिकेट की परीक्षा जिले की समन्वयक संस्था उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित हुई। 13 एमपी बटालियन एनसीसी नर्मदापुरम के कमान अधिकारी कर्नल सत्यप्रकाश सिंह के निर्देशानुसार व प्राचार्य सत्येंद्र उदयपुरे के मार्गदर्शन में आयोजित परीक्षा में जूनियर डिवीजन के 139 कैडेटस शामिल हुए। संस्था के एनसीसी अधिकारी ओम द्विवेदी ने बताया कि एनसीसी के ए सर्टिफिकेट के लिए आयोजित परीक्षा को दो भागों में कराया गया। पहले भाग में ड्रील टेस्ट के साथ मैप रीडिंग, फील्ड व बैटल क्राफ्ट तथा हथियार प्रशिक्षण से संबंधित ज्ञान को जाँचा गया। वही परीक्षा के दूसरे भाग में लिखित परीक्षा ली गई। परीक्षा में शामिल होने के लिए कैडेट को प्रशिक्षण वर्ष में 75 प्रतिशत उपस्थिति एवं एक कैंप करने की अनिवार्यता होती है। परीक्षा केंद्र पर उत्कृष्ट विद्यालय के कैडेटस के साथ सांदीपनि कृषि विद्यालय बैतूल बाजार व सांदीपनि विद्यालय मुलताई के केडेटस ने भी परीक्षा दी। परीक्षा का संचालन एनसीसी अधिकारी महेश कुमार यादव व एनसीसी अधिकारी ओम द्विवेदी द्वारा किया गया। सीनियर डिवीजन के एएनओ डॉ खुशाल देवघरे उपस्थित रहे। बटालियन से नायब सूबेदार सुरेन्दर सिंह एवं बीएचएम पूरन मिश्रा को बाहय परीक्षक नियुक्त किया गया था।

सर्टिफिकेट के हैं कई फायदे

एएनओ ओम द्विवेदी ने बताया कि 2 वर्ष की एनसीसी में एक कैडेट अनुशासन के साथ ही राष्ट प्रेम, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व व सामाजिक कल्याण जैसे गुणों को धारण करता है। परीक्षा में उत्तीर्ण कैडेटस को डीजी एनसीसी द्वारा ए सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जिसके विभिन्न स्तर पर बोनस अंक होते है। उक्त सर्टिफिकेट धारक को कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है, साथ ही सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भर्ती में विशेष छूट भी मिलती है।

अनिरूद्धाचार्य के आश्रम से वापस लाएंगे बैतूल की वृद्धा मां फूलवती

बालाजीपुरम में संस्थापक समेत सभी ने लिया संकल्प

बैतूल। बुजुर्ग अवस्था में जब माता-पिता को बच्चों के सहारे की आवश्यकता होती है तब दो बेटे और दो बेटियां होने के बाद भी एक मां को वृंदावन आश्रम जाना पड़े तो ये सिर्फ उसके बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बैतूल के लिए शर्म की बात है। ये कहना है भारत के पांचवेधाम श्री रूकमणि बालाजी मंदिर बालाजीपुरम बैतूल के संस्थापक सेम वर्मा का। गौरतलब है कि बैतूल की एक फूलवती माता जी पिछले दिनों वृंदावन में प्रसिद्ध संत अनिरूद्धाचार्य जी के गौरी गोपाल आश्रम पहुंची। यहां इन माताजी ने कथा के दौरान महाराज जी को बताया कि उनके बच्चे उन्हें नहीं रखते हैं इसलिए वो यहां आई हैं। अनिरूद्धाचार्य जी ने उन्हें अपने यहां रहने का आश्वासन दिया। इसका वीडियो

सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। बैतूल में भी यह चर्चा का विषय बना। यही वीडियो जब बालाजीपुरम संस्थापक सेम वर्मा ने देखा तो उन्होंने आज ब्रहोत्सव के दौरान घोषणा की कि बैतूल में जब मां रूकमणि के नाम पर इतना बड़ा धाम बना है तो यहां किसी भी घर में मां की इज्जत न होना शर्मनाक है। इसलिए जल्द ही पीड़ित माता के बच्चों को समझाइश देकर हर हाल में माताजी की घर वापसी सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके लिए मंदिर प्रबंधन ने अनिरूद्धाचार्य जी से भी संपर्क कर कार्रवाई आरंभ कर दी है। श्री वर्मा ने सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और समाज से भी सहयोग की अपील की है।

सहारा कंपनी में निवेश कर राशि डबल करने का झांसा देकर 5 लाख की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। सहारा कंपनी में निवेश कर राशि डबल करने का झांसा देकर 5 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस जनसंपर्क अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार 24 जनवरी को नानू मवासे पिता अमरलाल मवासे (67) निवासी ग्राम राजेगांव खापा, थाना सारणी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी सर्वदेव ओझा, निवासी अस्पताल कॉलोनी पाथाखेड़ा द्वारा सहारा कम्पनी में निवेश कर राशि डबल कर देने का झांसा देकर 4 अक्टूबर 2021 को चेक के माध्यम से कुल 05 लाख रुपये प्राप्त कर लिए। फरियादी द्वारा राशि निवेश करने के पश्चात आरोपी द्वारा सहारा कम्पनी में जमा की गई राशि की कोई रसीद प्रदान नहीं की गई। साथ ही जब फरियादी द्वारा बैंक से चेक संबंधी जानकारी प्राप्त की गई तो यह पाया गया कि उक्त राशि सहारा कम्पनी में जमा न होकर आरोपी के स्वयं के खाते में जमा हुई है। उक्त रिपोर्ट पर थाना सारणी में धारा 318(4) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना सारणी पुलिस द्वारा प्रकरण की गहन विवेचना की गई। विवेचना के दौरान थाना सारणी पुलिस द्वारा आरोपी सर्वदेव पिता बृम्हदेव ओझा, उम्र 55 वर्ष, निवासी अस्पताल कॉलोनी पाथाखेड़ा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को 25 जनवरी को न्यायालय बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक जयपाल इनवाती, उप निरीक्षक प्रीति पालेवार, प्रधान आरक्षक श्रीराम उईके, आरक्षक जितेंद्र जाट की सराहनीय भूमिका रही।

कार्यालय नगरपालिका परिषद, आमला जि.-बैतूल

E-mail ID-cmoamla@mpurban.gov.in Ph.-07147-285752

गणतंत्र दिवस समारोह 2026 राष्ट्रीय पर्व की समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं के साथ ही नगरवासियों से अपील करती है कि

1.जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ न बहायें। 2.नगरपालिका परिषद के समस्त करों का भुगतान समय से करें। 3.जन्म-मृत्यू एवं विवाह का पंजीयन समय पर अवश्य करायें। 4.नगर को साफ एवं स्वच्छ बनाएं रखने में सहयोग प्रदान करें। 5.अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण जैसी गतिविधियों में रोक लगावें। 6.बेटी है तो कल है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। 7.नगर को शौच मुक्त शहर बनाने में सहयोग करें।

श्री नितिन गाडरे अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद आमला
श्री किशोर माथनकर उपाध्यक्ष नगरपालिका परिषद आमला
श्री नितिन बिजवे मुख्य नपा अधिकारी

पार्षदगण- श्री सुनिल उईके, श्री संजय नंदलाल राठौर, श्री सुधीर अम्बाडकर, श्रीमती दिशा मयूर, श्री सूरजेकर, श्री राकेश शर्मा, श्रीमती सुधा लखनलाल नारे, श्रीमती अलका सुरेन्द्र मानकर, श्रीमती ममता राकेश धामोड़े, कुमारी खुशबू विजय अतुलकर, श्रीमती काशीबाई झनकलाल शेषकर, श्रीमती ओमवती विश्वकर्मा, श्रीमति पद्मनी भंबरकर, श्री अमित हुरमाड़े, श्री रोहित हारोड़े, श्रीमती शोभाप्रकाश देशमुख, नीलम लिखीराम साहू

एसआईआर-2026 में उत्कृष्ट कार्य के लिए बैतूल कलेक्टर को राज्यपाल ने किया सम्मानित

उप जिला निर्वाचन अधिकारी, एसडीएम आमला एवं बीएलओ आमला को भी मिला सम्मान

बैतूल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बैतूल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री पटेल ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल एवं संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम आमला शैलेंद्र बड़ोनिया तथा बीएलओ सुपरवाइजर रामप्रसाद पाल को भी उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल संजीव कुमार झा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान-2026 के अंतर्गत मतदाताओं के डिजिटाइजेशन कार्य को प्रभावी ढंग से पूर्ण करते हुए बैतूल जिले ने प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं आमला विधानसभा प्रदेश की पहली ऐसी विधानसभा बनी, जहाँ मतदाताओं का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन सबसे पहले पूर्ण किया गया। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी के सतत मार्गदर्शन, नियमित मॉनिटरिंग एवं समीक्षा के साथ-साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, सहायक बीएलओ तथा निर्वाचन कार्य में संलग्न समस्त अमले की कड़ी मेहनत और तत्परता से यह उल्लेखनीय उपलब्धि संभव हो सकी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का कैलेंडर घोषित होते ही निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से समन्वित प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप बीएलओ एप के माध्यम से मतदाताओं का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। इससे जिले में गणना पत्रकों का संधारण बिना किसी कठिनाई के सुनिश्चित हो सका।

कार्यालय नगर परिषद, भैंसदेही जिला-बैतूल

गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व की समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

श्री मनीष सोलंकी अध्यक्ष, नप. भैंसदेही

श्रीमति कुसुमसिंह ठाकुर उपाध्यक्ष, नप. भैंसदेही

श्री हितेष शाक्य सीएमओ, नप. भैंसदेही

पार्षदगण -जयसिंग कापसे, कृष्णा पिपरदे, निर्मला महाले, प्रीतासिंह कौशिक, लीला राठौर, सुषमा प्रजापति, ब्रम्हदेव कुबडे, तारा पाल, आशुतोष राठौर, सुरजितसिंह ठाकुर, महेश थोटेकर, उर्मिला मोहरे, परि विंध्यानी

अपील-1.समस्त करों का भुगतान समय पर कर नगर विकास में सहयोग प्रदान करें। 2. नगर को साफ एवं स्वच्छ बनायें रखें। 3. कचरा वाहन में गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग देवें। 4. खुले में शौच ना करे और न करने दे। 5. अपने घरो एवं दुकानो का कचरा सड़क एवं नाली में ना डाले। 6. जल को व्यर्थ न बहायें 8. एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगायें।

गणतंत्र दिवस- हमारा कर्तव्य

गणतंत्र दिवस विशेष

शिवप्रकाश

26 जनवरी को भारत अपने गणतंत्र का 76वां वर्ष हर्षोल्लास से मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपने संविधान को लागू किया था। 75 वर्षों की भारत की यह यात्रा चुनौतियों से भरी हुई, लेकिन एक सफल लोकतंत्र की कहानी है। हमारी इस सफलता में भारत के संविधान का महत्वपूर्ण योगदान है। संविधान सभा द्वारा अपना यह संविधान 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। हमने उस समय यह संकल्प दोहराया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय देने के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। हम अपनी-अपनी श्रद्धा एवं आस्थाओं का पालन करते हुए बंधुभाव के साथ राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। हमारे संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था कि भारत का संविधान दक्षिण अफ्रीका सहित कई अन्य उभरते लोकतंत्रों के लिए प्रेरणा बना है, क्योंकि इसने विविधता में सम्मान सिखाया है। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव के अवसर पर हम भारत के लोगों को भविष्य की चुनौतियों के प्रति सजग रहते हुए उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने पंचप्रण के आह्वान में भारतवासियों से सभी प्रकार की गुलामी से मुक्ति का आह्वान किया है। कुछ विदेशी विद्वानों द्वारा योजनाबद्ध पद्धति से भारतीय समाज में हमारी व्यवस्थाओं, इतिहास, महापुरुषों एवं संस्कृति के प्रति हीनता का भाव उत्पन्न किया गया, इसका परिणाम हुआ कि हमारा समाज आत्महीनता के भाव से ग्रसित हुआ है। हमारे राष्ट्र का आधार क्या है, किन मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे ऐसे विषयों पर संपूर्ण राष्ट्र संभ्रम में है। भारत ही दुनिया का ऐसा देश है जिसके नाम भी भारत/इंडिया दो है। यह स्थिति ही भारत के अनेक विवादों का कारण है। डॉ. एस. राधाकृष्णन का संविधान सभा का भाषण- 'राष्ट्रीयता निर्भर करती है, उस जीवन पद्धति पर जिसे चिरकाल से हम बरतते चले आ रहे है। यह जीवन पद्धति तो इस देश की निजी वस्तु है।' महात्मा विदुर जी ने कहा था कि 'संभ्रम की स्थिति में राजा,प्रजा सहित संपूर्ण राष्ट्र समाप्त हो जाता है।' गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के गौरव का स्मरण कर संभ्रमरहित अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर समाज के जागरण का संकल्प लें।

15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बदलते जनसांख्यिकी परिवर्तन पर चिंता व्यक्त की थी। जनसंख्या के इस असंतुलन के कारण भारत का विभाजन हम देख चुके। योजनाबद्ध पद्धति से अनेको माध्यमों से भारत में धार्मिक आधार पर जनसंख्या परिवर्तन को पुनः आकार देने का कार्य हो रहा है। घटती हिंदु जनसंख्या एवं उसके परिणाम पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हम प्रतिदिन होने वाली घटनाओं से अनुभव कर सकते है। मिस्र, तुर्की, ईरान, लेबनान, कोसोवो भी बढ़ती जनसंख्या के कारण समाप्त हुई अपनी प्राचीन संस्कृति के साक्षी है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री अगस्टकाम्टे ने इन्हीं अनुभवों के आधार पर कहा था कि जनसंख्या ही भाग्य है। हम भारत के लोग इन आसन्न खतरों को पहचानकर विदेशी घुसपैठियों को 'डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट' करने में सहायक बनकर लोकतंत्र को बचाने में सहभागी बने।

विश्व में भारत की बढ़ती शक्ति के कारण अनेक विदेशी शक्तियां, विदेश प्रेरित व्यक्ति एवं संस्थाएँ परेशान दिखाई दे रही है। इस परेशानी के कारण वह मान्यता प्राप्त संवैधानिक संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं को बदनाम करने का निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। अनेक देशों द्वारा प्रशंसित विश्व में अपना विशिष्ट महत्व रखने वाले भारतीय चुनाव आयोग एवं ईवीएम पर आरोप लगाना, सीएए का आधार लेकर भ्रम निर्माण करते हुए समाज में संघर्ष खड़ा करना, संविधान बदलने एवं आरक्षण हटाने जैसे आरोप लगाना, किसान आंदोलन के नाम पर होने वाली घटनाएं यह सब इसी के जीवंत प्रमाण है। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में प्रारंभ हुए आंदोलनो द्वारा चुनी हुई सरकारों को बदलने में भी इन्ही शक्तियों का हाथ बताया जाता है। जेन जेड के नाम पर भारत में भी वह यह स्वप्न संजोए हैं। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में कहा था कि यह अराजकता का व्याकरण है। उन्होंने कहा कि 'यह तथाकथित जनआंदोलन लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध प्रचार को हथियार के रूप में प्रयोग करने का प्रयास था।' भारत में विदेशी सहायता प्राप्त अनेक स्वयं सेवी संगठन इस अराजकता के पीछे सक्रिय है। अनेक देशों में परस्पर संघर्ष कराकर एवं आर्थिक साम्राज्यवाद के माध्यम से विश्व में अपने प्रभुत्व का समर्थन देखने वालों के लिए भारत को स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता के आधार पर विकसित एवं सुरक्षितबनाना ही उत्तर होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया प्रकल्प एक भारत - श्रेष्ठ भारत एकत्व की अनुभूति हम भारतवासियों को कराता है। काशी - तमिल संगमम् इसका जीवंत उदाहरण है। हम भारत के लोगों ने करोड़ों भारतवासियों को इस सत्य की अनुभूति कराने का सफल प्रयास करना है।

भारत की सरकार ने 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। 2014 से अब तक लगभग 2000 से अधिक नक्सली मारे गए है एवं लगभग 7000 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर संविधान में आस्था व्यक्त की है। हम सभी भारतवासियों को नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में होने वाले विकास एवं पुनर्वास में सहायक बनकर नक्सल मुक्त भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प में सहायक बनना होगा।

कट्टरवादी ताकतें सभी स्थानों पर अपने को पीड़ित दिखाकर अपनी पहचान बचाने के नाम पर अनेक षड्यंत्र कर रही हैं। बांग्लादेश में मकर संक्रांति का विरोध,अमेरिका के टैक्सास में अलग भूमि की मांग, मतांतरण एवं लव जेहाद के षड्यंत्र भारत सहित सभी स्थानों पर हम देख रहे है। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन द्वारा समाज में भय निर्माण करने का प्रयास हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं न्याय प्रणाली को चुनौती देना कुछ समूहों का स्वभाव ही बनता जा रहा है। राष्ट्र के हित में विचार करने वाले सभी राष्ट्र हितैषियों के लिए यह चिंता का विषय है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्य व्यक्ति की भागीदारी के लिये परिवारवाद से मुक्ति, आर्थिक योजना के क्रियान्वयन में प्रमाणिकता यह हमारे व्यवहार एवं निर्णयों का विषय बनना चाहिए। सरकारों की सफलता का आधार विकास एवं समाज की खुशहाली बने, न कि उनका मूल्यांकन जाति एवं क्षेत्र के आधार पर हो। इसके कारण समाज का आंतरिक वातावरण परस्पर सद्भाव एवं बंधुता से युक्त बनेगा। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर संवैधानिक मूल्यों का पालन कर, चुनौतियों के प्रति जागरूक रहते हुए हम अपने कर्तव्यों का पालन करे, यही हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) श्रीमती अमृत राज ने बैंगलोर में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया

बैंगलोर। कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), नई दिल्ली की प्रमुख विकास आयुक्त श्रीमती अमृत राज ने हाल ही में बैंगलोर में मीरास फाउंडेशन द्वारा आयोजित विशेष हस्तशिल्प प्रदर्शनी का दौरा किया। इस भ्रमण के दौरान उन्होंने देश के विभिन्न कोनों से आए मास्टर शिल्पकारों की कला का अवलोकन किया और उनकी उत्कृष्ट कारीगरी की सराहना की। प्रदर्शनी के दौरान एक महत्वपूर्ण पड़ाव मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध 'बाग प्रिंट' कला का स्टाल रहा। श्रीमती अमृत राज ने बाग प्रिंट के विश्वविख्यात कलाकार, शिल्प गुरु मोहम्मद युसूफ़ खत्री से मुलाकात की। उन्होंने खत्री जी द्वारा तैयार किए गए अद्भुत नमूनों को न केवल बारीकी से देखा, बल्कि उनकी कलात्मक निपुणता की भूरि-भूरि प्रशंसा भी की।

हस्तशिल्प के भविष्य पर मंथन

मुलाकात के दौरान, विकास आयुक्त और शिल्प गुरु युसूफ़ खत्री के बीच भारतीय हस्तशिल्प के विकास, कलाकारों के उत्थान और वैश्विक स्तर पर बाग प्रिंट की पहचान को और सुदृढ़ करने के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। श्रीमती अमृत राज ने हस्तशिल्प क्षेत्र में आ रहे नवाचारों और शिल्पकारों की समस्याओं को समझते हुए विभाग की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर श्रीमती अमृत राज ने कहा कि शिल्प गुरु मोहम्मद युसूफ़ खत्री जैसे समर्पित कलाकार हमारी सांस्कृतिक विरासत के सच्चे रक्षक हैं। प्रदर्शनी में शिल्पकार मोहम्मद काज़िम खत्री के डिज़ाइनर उत्पादों का विशेष आकर्षण रहा।

महाकाल लोक में 488 होमगार्ड जवान होंगे तैनात

उज्जैन में मंदिर की सुरक्षा के लिए ईएसबी करेगा भर्ती; जवानों का कहीं और नहीं होगा ट्रांसफर

भोपाल (नप्र)। महाकाल लोक और महाकाल महाराज के दर्शन के लिए उमड़ने वाली लाखों की भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अब होमगार्ड के जवानों को मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के बाद महाकाल मंदिर के लिए होमगार्ड की 4 विशेष कंपनियों के गठन के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है।

होमगार्ड मुख्यालय भोपाल से इनकी भर्ती के लिए आधिकारिक मंजूरी का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा जा चुका है। यह भर्ती राज्य स्तर पर कर्मचारी चयन मंडल के जरिए की जाएगी। गृह विभाग इन पदों के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी करने के निर्देश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) को देने वाला है।

जवानों का कहीं और नहीं होगा ट्रांसफर-होमगार्ड के इस स्पेशल कैडर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन जवानों का ट्रांसफर कहीं और नहीं होगा। ये जवान कॉल ऑफ और कॉल ऑन से मुक्त रहेंगे। होमगार्ड में भर्ती होने वाले ऐसे जवान अपने पूरे सेवाकाल के दौरान केवल महाकाल मंदिर में ही सेवाएं देंगे।

इससे उन्हें मंदिर की भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा बारीकियों का विशेषज्ञ बनने में मदद मिलेगी। मामले में होमगार्ड के अफसरों का कहना है कि महाकाल मंदिर के लिए होमगार्ड की चार कंपनियों की भर्ती के लिए मंजूरी मिली हैं। 488 पदों पर ESB के जरिए भर्ती होगी। गृह विभाग को विज्ञापन जारी करने के लिए पत्र लिखा है।

हर रोज लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं

उज्जैन-महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। यहां हर रोज औसतन एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। इसे देखते हुए यह नई होमगार्ड फोर्स मंदिर परिसर की सुरक्षा के साथ यात्रियों की सहायता के लिए भी मुस्तैद रहेगी।

इन जवानों को होमगार्ड को नियुक्ति से पहले बेसिक ट्रेनिंग के साथ ही भीड़ प्रबंधन के गुर भी सिखाए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन हो सकें। अभी महाकाल मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों के हवाले है।

सुरक्षा में लगने वाले होमगार्ड

कुल पद 488 होंगे।

कुल कंपनियां 4 रहेगी।

हर कंपनी में 122 जवान होंगे।

केवल महाकाल मंदिर, मुख्य परिसर और महाकाल लोक में सेवा देंगे। जवानों का वेतन महाकाल मंदिर ट्रस्ट देगा

3 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई जाएगी।

निजी सुरक्षा व्यवस्था बंद होगी।

दूषित पानी से कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष की मौत

इंदौर में मृतकों का आंकड़ा 28 पर पहुंचा; दो और मरीजों की हालत गंभीर

इंदौर (नप्र)। इंदौर में दूषित पानी से 28वीं मौत हुई है। भागीरथपुरा निवासी रिटायर्ड शिक्षक राजाराम बौरासी (75) ने रविवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बौरासी कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष भी थे।

परिजन ने बताया कि राजाराम बौरासी को शुक्रवार को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई थी। हालत बिगड़ने पर पहले स्थानीय डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन आराम नहीं मिला। इसके बाद शनिवार सुबह उन्हें सरकारी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।उधर, स्वास्थ्य विभाग ने कहा- 2018-19 की एंजियोग्राफी रिपोर्ट के अनुसार राजाराम बौरासी हृदय रोग से पीड़ित थे। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या भी थी। उपलब्ध चिकित्सकीय दस्तावेजों में उल्टी-दस्त की पुष्टि नहीं होती है।फिलहाल, दूषित पानी से बीमार 10 लोग सरकारी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 4 आईसीयू में हैं। इनमें से एक महिला और एक पुरुष मरीज की स्थिति चिंताजनक है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन के हामू खेड़ी में शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित बच्चों के हायर सेकेंडरी स्कूल में 'हर क्षमता को उड़ान' कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए।

इंदौर पुलिस कमिश्नर सहित 4 पुलिस अफसरों को राष्ट्रपति पदक

गणतंत्र दिवस पर होंगे सम्मानित, 17 अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक मिलेगा

भोपाल (नप्र)। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने पुलिस, फायर, होमगार्ड व अन्य सेवाओं के लिए पदकों की घोषणा कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश के लिए यह उपलब्धि खास रही है। जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, मध्य प्रदेश पुलिस के 21 अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक (पीएसएम) और सराहनीय सेवा पदक (एमएसएम) से सम्मानित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के अफसरों को मिलेंगे 21 पदक-राज्यवार जारी आंकड़ों के मुताबिक 4 अफसरों को राष्ट्रपति पदक; एमपी के चार पुलिस अफसरों को प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विशड सर्विस यानी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा।

17 पुलिस अफसरों को सराहनीय सेवा पदक: एमपी के 17 पुलिस अफसरों को सराहनीय सेवा पदक यानी मेडल फॉर मेरिटॉरियस सर्विस से सम्मानित किया जाएगा। इस तरह कुल 21 पदक मध्य प्रदेश के खाते में आए हैं, जो राज्य पुलिस के अनुशासन, कार्यक्षमता और निरंतर सेवा के लिए ये सम्मान प्रदान किए जाएंगे।

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

छत्तीसगढ़ से कौन होगा नितिन नबीन की टीम में

छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे नितिन नबीन अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नितिन नबीन अब अपनी टीम बनाने वाले हैं, ऐसे में चर्चा होने लगी है कि छत्तीसगढ़ से नितिन नबीन की टीम में कौन जाएगा ? बताते हैं कि नितिन नबीन की टीम का हिस्सा बनने के लिए भाजपा के कई नेता दौड़ में हैं, पर सबसे चर्चित नाम विधायक सुशांत शुक्ला का बताया जा रहा है। सुशांत शुक्लाभाजयुमो में नितिन नबीन के साथ काफी साल काम किए हैं। सुशांत शुक्ला युवा नेता और तेजतर्रार भी हैं। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सुशांत शुक्ला नितिन नबीन की टीम में मंत्री बन सकते हैं।

नितिन नबीन की टीम के लिए सौरभ सिंह का नाम भी चर्चा में हैं। पूर्व विधायक सौरभ सिंह अभी राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं। सौरभ सिंह बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस होते हुए भाजपा में आए हैं। कुछ पुराने भाजपा नेता भी नितिन नबीन की टीम में जगह पाने के लिए प्रयासरत बताए जाते हैं। मैदानी इलाके की एक महिला नेत्री का नाम भी सुर्ख़ियों में है। यह महिला नेत्री पहले भी संगठन में रह चुकी हैं। नितिन नबीन की टीम के लिए मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा का नाम भी लोगों की जुबान पर है। लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि पंकज झा राष्ट्रीय टीम में मीडिया या कार्यालय की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। उम्मीद है कि फ़रवरी में परिदृश्य साफ़ हो जाएगा।

नहीं चली मंत्री जी की

कहते हैं कि राज्य के एक मंत्री जी समग्र शिक्षा में संचालक और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में प्रबंध संचालक के पद पर अपनी पसंद के अफसर की पोस्टिंग करवाना चाहते थे। बताते हैं मंत्री जी ने इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री सचिवालय को नोटशीट भेजी थी, पर मंत्री जी की मंशा के उलट फैसला हो गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2009 बैच की आईएएस किरण कौशल को समग्र शिक्षा का आयुक्त और पाठ्य पुस्तक निगम का प्रबंध संचालक बना दिया।

डॉ. प्रियंका शुक्ला के केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण आयुक्त समग्र शिक्षा और पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक का पद रिक्त हो गया था। समग्र शिक्षा और पाठ्य पुस्तक निगम स्कूल शिक्षा के अधीन है। पाठ्य पुस्तक निगम स्वतंत्र निकाय है। निगम में अध्यक्ष और कार्यकारिणी ही सारे फैसले लेते हैं। चर्चा है कि मंत्री जी की पसंद को नजरअंदाज कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झटका दे दिया और संदेश भी दे दिया कि प्रशासन तो उनकी मर्जी से ही चलेगा।

तमनार घटना पर एक्शन?

सरकार ने 2014 बैच के आईपीएस दिव्यांग पटेल को रायगढ़ के एसपी के पद से हटाकर एसपी रेल पुलिस बना दिया। उनके तबादले को तमनार की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे रायगढ़ एसपी रहते दिव्यांग पटेल को दो साल हो गए थे। पिछले महीने तमनार में ग्रामीण जिंदल पावर लि की जनसुनवाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और उग्र हो गए। पुलिस स्थिति का आंकलन नहीं कर पाई। तमनार में पुलिस की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। पुलिस प्रशासन का इकबाल ही नहीं दिखा। तमनार में कुछ आंदोलनकारियों ने एक महिला सिपाही के कपड़े फाड़ दिए और महिला थाना प्रभारी के साथ भी दुर्व्यवहार किया। इससे पुलिस की काफी किरकिरी हुई और सरकार की भी बदनामी हुई। कहते हैं सरकार ने तत्काल कोई कदम न उठाते हुए मामला शांत होने पर एक्शन लिया। एसपी के बाद अब कुछ प्रशासनिक अफसरों पर भी गाज गिरने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जनसुनवाई की जिम्मेदारी प्रशासनिक अफसरों पर होती है।

बड़े विभाग महिला आईएएस अफसरों के जिम्मे

छत्तीसगढ़ में करीब आधे दर्जन बड़े विभाग महिला आईएएस अफसरों के जिम्मे है। 1994 बैच की आईएएस ऋचा शर्मा वन विभाग की एसीएस हैं, तो 1997 बैच की आईएएस निहारिका बारिक पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव हैं। 2001 बैच की आईएएस शहला निगार कृषि उत्पादन आयुक्त हैं। शहला निगार इसी महीने प्रमुख सचिव के तौर पर प्रमोट हुई हैं। सचिव के स्तर पर रहते हुए सरकार ने उन्हें कृषि उत्पादन आयुक्त की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी थी। कृषि उत्पादन आयुक्त के पास पशुपालन, डेयरी विकास, मछली पालन और हार्टिकल्चर जैसे विभाग भी होते हैं। 2003 बैच की आईएएस अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले खाद्य और राजस्व विभाग संभाल रही हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बड़ा टास्क होता है। धान खरीदी का जिम्मा खाद्य विभाग के पास ही रहता है, इसमें खाद्य सचिव की बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। 2007 बैच की आईएएस शम्मी आबिदी महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव हैं। राज्य में महतारी वंदन योजना के तहत लाखों महिलाओं को सहायता मिल रही है और भाजपा सरकार में इस योजना की बड़ी भूमिका है। महिला और बाल विकास विभाग को भारत सरकार से मदद भी काफी मिलती है, ऐसे में इस विभाग का सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका है। कई विभागों में संचालक भी महिला आईएएस अफसर हैं।

मंत्री का पुत्र सुपर मंत्री

कहते हैं राज्य के एक मंत्री का पुत्र सुपर मंत्री बन गया है। बताते हैं मंत्री के ई आफिस का पासवर्ड भी उसी के पास रहता है। मंत्री पुत्र चाहता है, तो फाइल आगे बढ़ती है, अन्यथा नहीं। खबर है कि मंत्री पुत्र ही स्टाफ को दिशा-निर्देश देते हैं। खबर है कि मंत्री जी कई विभागों की कमान संभाले हुए हैं, पर जबसे वे मंत्री की कुर्सी पर विराजे हैं, तब उनके कई सहयोगी उन्हें बाय-बाय कर गए हैं या फिर मंत्री जी ने ही उनकी छुट्टी कर दी है। यहाँ तक की मंत्री जी ने अपने खासमखास को भी नहीं बख्शा। बताते हैं कि विश्वासघात की सूचना पर मंत्री जी सख्त एक्शन ले लेते हैं। चर्चा है मंत्री जी ने अपने एक पुराने साथी को अपने से जोड़ा था, पर पुराना साथी उनसे तालमेल नहीं बैठा पाया और जल्द ही उनसे विदाई ले ली। हल्ला है कि मंत्री स्टाफ के कई लोग मंत्री पुत्र के फरमान से असहज महसूस करने लगे हैं और नए ठौर तलाशने लगे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है ?

मुख्यमंत्री साय ने चलाई अपनी मर्जी

कहते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में पुलिस कमिश्नर मॉडल को लेकर किसी की नहीं सुनी। कैबिनेट ने जो पहले से तय किया था, उसे ही लागू किया। कहा जाता है गृह मंत्री विजय शर्मा समेत कुछ अन्य मंत्री चाहते थे कि रायपुर के पुलिस कमिश्नर के दायरे में नया रायपुर और कुछ ग्रामीण इलाका आ जाय। बताते हैं मुख्यमंत्री ने संशोधन से पहले मॉडल लागू करने पर जोर दिया। खबर है कि मुख्यमंत्री ने साफ़ कर दिया कि 23 जनवरी से रायपुर में पुलिस कमिश्नर मॉडल लागू करना प्राथमिकता में है, क्षेत्राधिकार में विस्तार पर आगे फैसला लिया जाएगा। रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला बनाए गए हैं। संजीव शुक्ला रायपुर के तासीर और इलाके से अच्छे से वाकिफ हैं। रायपुर में पिछले कुछ वर्षों से साइबर क्राइम से लेकर दूसरे तरह के अपराध बढे हैं। ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि अब रायपुर शहर के कानून-व्यवस्था को एक आईजी, एक डीआईजी, छह आईपीएस, आठ एडिशनल एसपी, 16 डीएसपी और 32 राजपत्रित दुरुस्त करेंगे। थानों में स्टाफ भी बढ़ाए जाने की खबर है।

अब बलौदाबाजार-भाटापारा का कलेक्टर कौन बनेगा

सरकार ने जगदलपुर के कलेक्टर एस हरीश की जगह 2017 बैच के आईएएस आकाश छिकारा को जगदलपुर का कलेक्टर बना दिया है। आकाश छिकारा गरियाबंद और जांजगीर-चांपा के कलेक्टर रह चुके हैं। एस हरीश केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। बलौदाबाजार-भाटापारा के कलेक्टर दीपक सोनी भी केंद्र सरकार में जाने वाले हैं। भारत सरकार ने उनकी प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर की जिम्मेदारी किसको मिलती है, इस पर नजर है। रायपुर नगर निगम के कमिश्नर रहते मयंक चुतर्वेदी और अबिनाश मिश्रा को कलेक्टर बनने का मौका मिल चुका है। इस कारण बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर के लिए रायपुर नगर निगम के कमिश्नर विश्वदीप का नाम भी चर्चा में है। विश्वदीप 2019 बैच के आईएएस हैं।

कैसे मनाएं 77वां गणतंत्र दिवस

26 जनवरी भारत के इतिहास की वह तारीख है, जब देश ने खुद को एक संप्रभु गणराज्य घोषित किया। हरा साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति तिरंगा ध्वज फहराकर सलामी देते हैं। गणतंत्र दिवस पर परेड का आयोजन होता है। देशभक्ति और राज्यों की समृद्धता को दिखाने के लिए झांकियां निकाली जाती हैं। इस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है। ऐसे में ये बच्चों के लिए छुट्टी वाला दिन हो सकता है।

गणतंत्र दिवस केवल परेड देखने या छुट्टी मनाने तक सीमित नहीं है। ये संविधान, लोकतंत्र और नागरिक जिम्मेदारियों की याद करने का अवसर है। सही तरीके से राष्ट्रीय पर्व मनाना जितना ज़रूरी है, उतना ही जरूरी है यह जानना कि 26 जनवरी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें

घर, स्कूल या सोसायटी में तिरंगा फहराएं, लेकिन पूरी मर्यादा और नियमों के साथ।

संविधान को समझें

कम से कम संविधान की प्रस्तावना पढ़ें या बच्चों को उसका अर्थ समझाएं।

परेड और कार्यक्रम देखें

दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड देश की सैन्य, सांस्कृतिक और तकनीकी ताकत दिखाती है।

देशभक्ति से जुड़ा कंटेंट साझा करें

सोशल मीडिया पर अर्थपूर्ण संदेश, शायरी या तथ्य साझा करें, सिर्फ फॉरवर्डेड मैसेज न भेजें।

बच्चों को शामिल करें

ड्रॉइंग, भाषण, कविता या तिरंगा थीम एक्टिविटी के जरिए उन्हें देश से जोड़ें।

जनवरी को क्या नहीं करें?

- तिरंगे का अपमान न करें। फटा हुआ, जमीन पर पड़ा या गलत रंगों वाला झंडा इस्तेमाल न करें।
- देशभक्ति को मज़ाक न बनाएं। फेक न्यूज़, भड़काऊ पोस्ट या राजनीतिक तंज से बचें।
- सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। रैली या जश्न के नाम पर तोड़फोड़ देशभक्ति नहीं है।
- सिर्फ छुट्टी समझकर दिन न गंवाएं। गणतंत्र दिवस पिकनिक नहीं, राष्ट्रीय चेतना का दिन है।
- शराब या असंयमित व्यवहार से बचें। यह दिन संयम, गरिमा और अनुशासन का प्रतीक है।

सेना की परेड कैसे बनी गणतंत्र दिवस की शान

इस साल भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जिसकी थीम है स्वर्णिम भारत-विरासत और विकास. गणतंत्र दिवस की परेड में भारत अपनी सेनाओं की ताकत, तकनीकी तरक्की और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करता है. इस दौरान सेना की खास परेड होती है. आइए जान लेते हैं कि सेना की परेड कैसे गणतंत्र दिवस की शान बन गई?

हर साल 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस मौके पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है. इसमें पूरे भारत की तस्वीर झांकियों के रूप में सामने आती है तो देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करता है. इससे दुनिया को यह संदेश जाता है कि भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत न करे तो देशवासियों को यह आश्वासन मिलता है कि देश अपनी रक्षा करने में सक्षम है. इस साल भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जिसकी थीम है स्वर्णिम भारत-विरासत और विकास. आइए जान लेते हैं कि सेना की परेड कैसे गणतंत्र दिवस की शान बन गई? अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भारत ने 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान अंगीकार किया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था. हर साल इसी उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत अपनी सेनाओं की ताकत, तकनीकी तरक्की और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करता है. इस दौरान सेना की खास परेड होती है, जो रायसीना हिल से शुरू होकर कर्तव्य पथ (पहले राजपथ) पर इंडिया गेट होते हुए लालकिले तक जाती है.

पहली बार तीन हजार जवानों ने किया था मार्च इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया ऑफ्टर गांधी में लिखा है कि पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के सामने सशस्त्र सेनाओं के तीन हजार जवानों ने मार्च किया था. 31 तोपों की सलामी दी गई थी और वायुसेना के विमानों ने करतब दिखाए थे. पहली परेड का आयोजन जहां एक स्टेडियम में किया गया था, वहीं अगले ही साल इसे राजपथ पर शिफ्ट कर दिया गया. इसके बाद जल्द ही केंद्र सरकार राज्यों को भी इसमें हिस्सेदारी के लिए आमंत्रित करने लगी और सांस्कृतिक प्रदर्शनी भी परेड का हिस्सा बन गई. इससे परेड अनेकता में एकता का प्रतीक बन गई.

झांकियों के साथ बढ़ती गई परेड

जैसे-जैसे राज्य अपनी झांकियां परेड में भेजने लगे, परेड और भी लंबी और कलरफुल होती गई. दिल्ली से दूर रहने वालों के लिए यह परेड आज भी आकर्षण का केंद्र है. अब तो इसमें कई सरकारी विभाग भी हिस्सा लेते हैं. वास्तव में भारतीयों के लिए शुरुआत में यह परेड एक शक्तिशाली गणतंत्र के रूप में अपने अस्तित्व को दर्शाने का प्रतीक थी. इसके लिए अंग्रेजी सरकार से भी कुछ प्रेरणा मिली थी, जो अपने ग्रैंड रिसेप्शन और प्रोसेशन के लिए जानी जाती थी और जिससे भारतीय काफी हद तक परिचित थे.

अलग-अलग क्षेत्रों में तरक्की का प्रदर्शन

समय के परेड में भव्यता आती गई. जैसे-जैसे भारत अलग-अलग क्षेत्रों में तरक्की करता रहा, उसका प्रदर्शन भी इसका हिस्सा बनता रहा. परेड में तीनों सेनाओं की टुकड़ियां, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां, एनसीसी के कैडेट तो कदमताल करते ही हैं, भारतीय सेनाओं के पास मौजूद अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी किया जाता है. परेड का मुख्य आकर्षण भी सेना के टैंकों से लेकर मिसाइलें तक होती हैं. ये जब राष्ट्रपति को सलामी देती हैं तो पूरा देश जज्बे से ओतप्रोत हो जाता है. हवा में करतब दिखाते वायुसेना के विमान हर किसी को रोमांचित कर देते हैं.

जब 26 नवंबर को तैयार हो गया था संविधान, तो क्यों किया गया 26 जनवरी का इंतजार?

भारत के लोकतंत्र की नींव हमारा संविधान है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हुआ। ऐसे में अक्सर एक दिलचस्प सवाल लोगों के मन में उठता है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास की एक घटना के बारे में जानना होगा। आइए जानें क्यों हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया।

पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक संकल्प

इस कहानी की शुरुआत संविधान बनने से 20 साल पहले, यानी 1929 में होती है। उस समय लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस यानी अर्ध-स्वतंत्रता की मांग छोड़कर पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था।

पहला गणतंत्र दिवस - 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन भारतीयों ने पहली बार तिरंगा फहराया और अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने की शपथ ली। 1930 से लेकर 1947 तक, हर साल 26 जनवरी को ही भारत के प्रतीकात्मक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता रहा।

15 अगस्त और 26 जनवरी का कॉर्डिनेशन

जब 1947 में भारत असल में आजाद हुआ, तो वह तारीख 15 अगस्त थी। इसलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन संविधान निर्माताओं, खासकर पंडित नेहरू और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के मन में उस 26 जनवरी की तारीख के प्रति गहरा सम्मान था, जिसने दो दशकों तक भारतीयों में आजादी की अलख जगाए रखी थी। वे नहीं चाहते थे कि 26 जनवरी जैसी ऐतिहासिक तिथि इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाए। इसलिए, यह तय किया गया कि भले ही संविधान 26 नवंबर 1949 (संविधान दिवस) को तैयार हो गया है, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा, ताकि इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए। इसलिए 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया और हमारा देश गणतंत्र बना। तब से हर साल 26 जनवरी को बड़ी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।

भारतवासी 26 जनवरी को 77 वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन वर्ष 1950 को पूरे देश में उत्साह और गर्व का माहौल था। इस दिन भारत का संविधान आधिकारिक तौर पर लागू हुआ और भारत को गणराज्य घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में हर साल गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत हुई। अब पूरे देश के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों के अलावा कई जगहों पर देशप्रेम की भावना के साथ गणतंत्र दिवस का पर्व खास समारोह के तौर पर मनाया जाता हैं लेकिन पहले साल गणतंत्र दिवस को कैसे मनाया गया, उस समय देश का माहौल कैसा था और कहां गणतंत्र दिवस का उत्सव सबसे पहले मनाया गया, ये जानना भी दिलचस्प होगा।

पहली बार कहां मनाया गया था गणतंत्र दिवस

पहला गणतंत्र दिवस समारोह दिल्ली के इरविन स्टेडियम (वर्तमान में राष्ट्रीय स्टेडियम) में आयोजित हुआ था। यह उस समय का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव था, जिसमें भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय ध्वज फहराया और परेड का नेतृत्व किया।

कैसे मनाया गया था पहला गणतंत्र दिवस

26 जनवरी 1950 को सुबह 10.18 बजे भारत का संविधान लागू किया गया। यह दिन 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस के संकल्प के कारण चुना गया था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में 26 जनवरी 1950 को शपथ ली। उन्होंने गवर्नमेंट हाउस जो कि अब राष्ट्रपति भवन है, में तिरंगा झंडा फहराया।

परेड और झांकी

पहली बार दिल्ली में भारतीय सेना की परेड आयोजित हुई, जिसमें भारत की ताकत और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया गया। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना ने भाग लिया। पहला गणतंत्र दिवस भारत की स्वतंत्रता के बाद एक और ऐतिहासिक कदम था, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया।

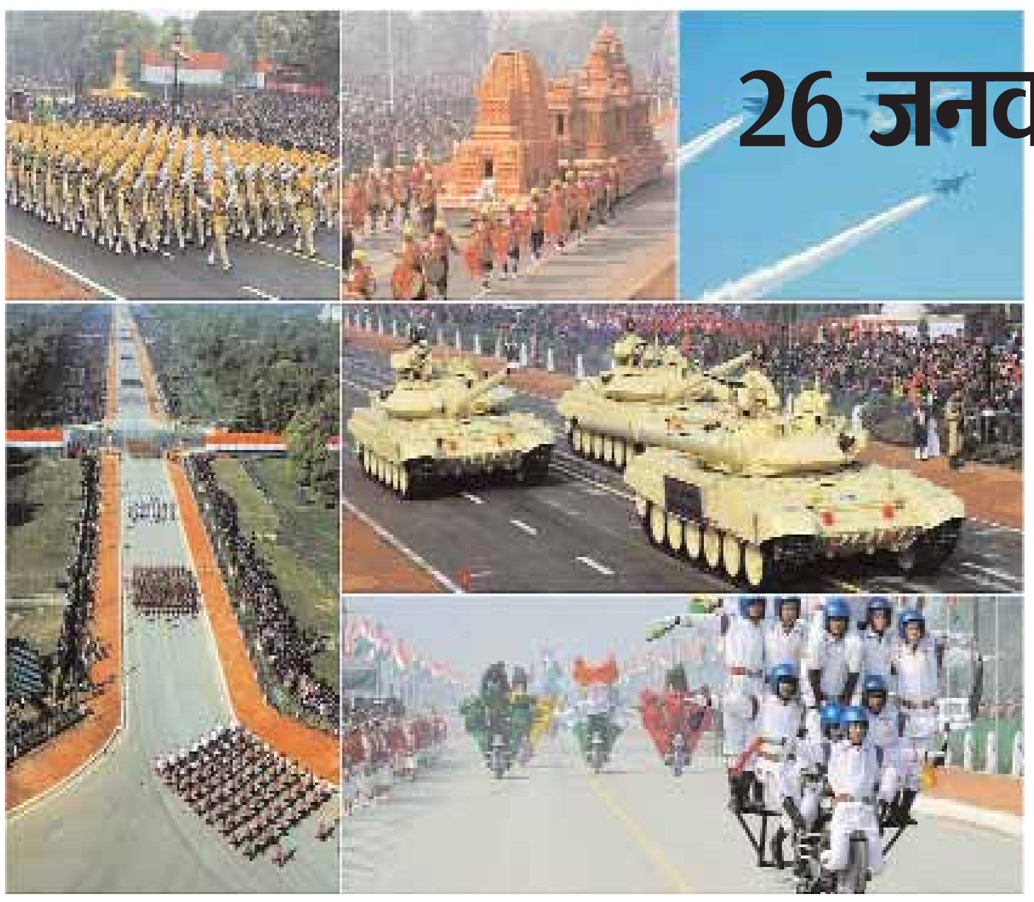

26 जनवरी पर क्यों नहीं फहराया जाता तिरंगा?

भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं जाता, बल्कि खोला जाता है। इसका कारण यह है कि भारत पहले ही आज़ाद हो चुका था। तिरंगा खोलना संविधान के लागू होने, लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश के गणराज्य बनने के सम्मान का प्रतीक माना जाता है

भारत में 26 जनवरी का दिन केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक पहचान का प्रतीक है। हर साल इस दिन गणतंत्र दिवस पूरे सम्मान और गर्व के साथ मनाया जाता है। 1950 में इसी तारीख को भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसने भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप दिया। ये दिन देश के नागरिकों को ये याद दिलाता है कि आजादी केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। गणतंत्र दिवस का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि ये संविधान द्वारा दिए गए समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों को रेखांकित करता है।

परेड, झांकियां और तिरंगे का गौरव

गणतंत्र दिवस पर देशभर में भव्य परेड, सांस्कृतिक झांकियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन सबके बीच सबसे खास क्षण होता है तिरंगे का औपचारिक प्रदर्शन, जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध देता है।

26 जनवरी पर तिरंगा फहरता है या खोला जाता है?

अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है या खोला जाता है। दरअसल, 26 जनवरी को तिरंगा फहराया नहीं जाता, बल्कि खोला जाता है, जिसे अंग्रेजी में फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है।

क्यों खोला जाता है राष्ट्रीय ध्वज?

गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा पहले से ही ध्वज स्तंभ के शीर्ष पर बंधा होता है। उसे रस्सी से ऊपर चढ़ाने की बजाय सिर्फ खोलकर फैलाया जाता है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ये सम्मान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रगान और औपचारिक समारोह होते हैं।

आजादी और संविधान के सम्मान की परंपरा

भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो चुका था, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसलिए इस दिन झंडा फहराना नहीं, बल्कि खोलना इस बात का प्रतीक है कि देश पहले से आजाद था और अब उसने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया।

झंडा फहराना बनाम झंडा खोलना

झंडा फहराना - इस प्रक्रिया में झंडा नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता है। ये स्वतंत्रता और गुलामी से मुक्ति का प्रतीक है और मुख्य रूप से 15 अगस्त को किया जाता है।

झंडा खोलना - इसमें झंडा पहले से ऊपर लगा होता है और उसे केवल खोला जाता है। ये संविधान, लोकतंत्र और गणराज्य बनने के गौरव को दर्शाता है, जो 26 जनवरी की पहचान है।

याद रखने वाली बात

अगली बार जब गणतंत्र दिवस आए, तो ये जरूर याद रखें कि उस दिन तिरंगा फहराया नहीं जाता, बल्कि खोला जाता है। ये परंपरा भारत की संवैधानिक यात्रा और गणराज्य बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि को सम्मान देने का प्रतीक है।